श्रीरामसेतु के बारे में सम्पूर्ण जानकारी

सारा भारत एक स्वर, एक प्राण से बोला

रामसेतुं रक्षतु

वानराणां हि सा तीर्णा वाहिनी नलसेतुना। तीरे निविविशे राज्ञो बहुमूलफलोदके।।

(धीरे-धीरे वानरों की सारी सेना नल के बनाये हुए पुल से समुद्र के उस पार पहुंच गयी।
राजा सुग्रीव ने फल, मूल और जल की अधिकता देख सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाला।।)

(वाल्मीकि रामायण, युद्धकाण्ड, सर्ग २२-८७)

पूज्य सरसंघचालक श्री कुप्. सी. सुदर्शन ने कहा-

उठो हिन्दुओ, इस संकट में एकता दिखाओ रामसेतु तोड़ा तो सारा देश आन्दोलित होगा

संप्रग सरकार का 'उपहार'

राम नवमी के दिन रामसेतु तोड़ने के लिए एक्सकेवेटिंग उत्खनन नौका रवाना

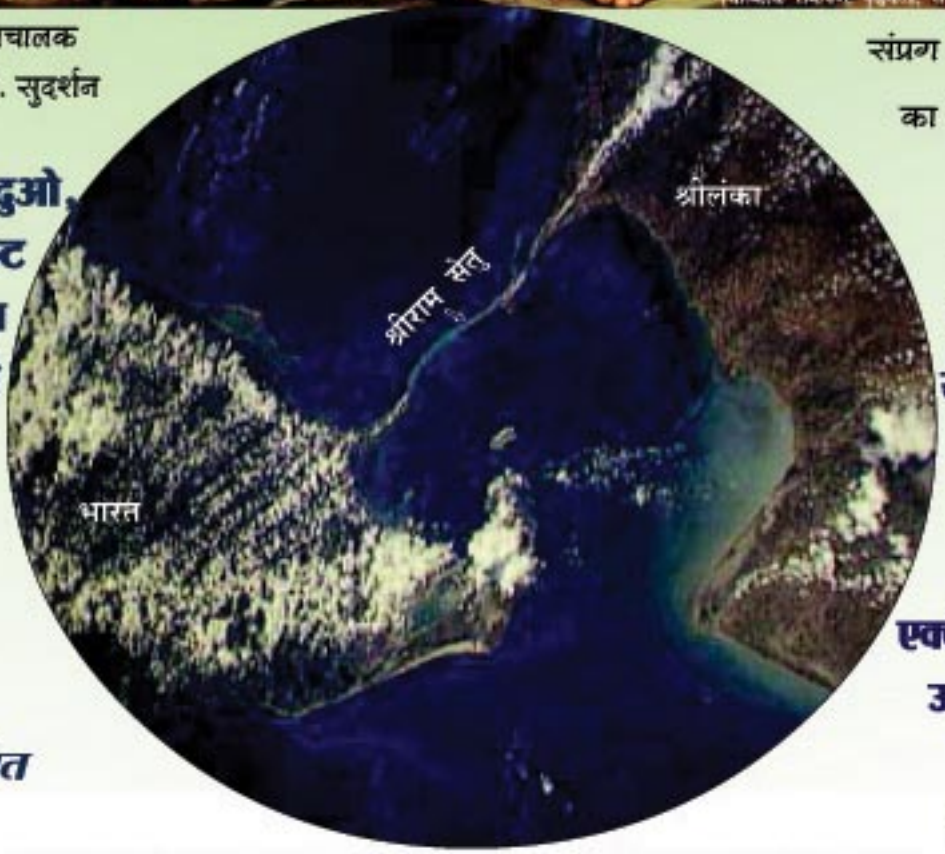

अमरीकी अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था 'नासा' द्वारा लिया गया उपग्रह चित्र। भारत (बाएं) और श्रीलंका के बीच राम सेतु (पतली रेखा जैसा) दर्शनीय है

रा.स्व.संघ की अ.भा. प्रतिनिधि सभा ने कहा-

राम सेतु बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान करें

लखनऊ बैठक में रा.स्व.संघ के सरकार्यवाह मोहनराव भागवत

गत ९ मार्च से ११ मार्च तक लखनऊ में रा.स्व.संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अ.भा. प्रतिनिधि सभा द्वारा श्रीराम सेतु के बारे में पारित प्रस्ताव के मुख्य अंश यहां प्रस्तुत हैं। -सं.

प्रस्ताव क्र. २

परियोजना मार्ग बदलें- राम सेतु बचाएं

भगवान राम द्वारा समुद्र पार करने के लिए निर्मित 'राम सेतु' से जुड़ी करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं को निर्लज्जतापूर्वक कुचलते हुए भारत सरकार के अधिकारी विवादास्पद 'सेतु समुद्रम् नहर परियोजना' के क्रियान्वयन की हठ पर अड़े हुए हैं। अ.भा. प्रतिनिधि सभा उनकी इस दुराग्रही व उतावली प्रवृत्ति की तीव्र भर्त्सना करती है। केन्द्रीय जहाजरानी मंत्री द्वारा सेतु समुद्रम् नहर परियोजना का विरोध करने वालों को 'राष्ट्रविरोधी' करार देने वाले वक्तव्य का भी प्रतिनिधि सभा कड़ा विरोध करती है।

प्रतिनिधि सभा मंत्री महोदय सहित अन्य अधिकारियों को यह स्पष्ट कर देना चाहती है

इस सभा का सरकार को यह सत्परामर्श है कि वह रामनाथपुरम् जिला न्यायालय द्वारा निर्देशित सुझावों के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का अविलंब गठन कर उसे परियोजना का वैकल्पिक मार्ग तैयार करने का निर्देश दे, जिससे देश के वाणिज्यिक लक्ष्यों की पूर्ति होने के साथ-साथ पवित्र राम सेतु को भी नष्ट होने से बचाया जा सके।

प्रतिनिधि सभा देशवासियों का आह्वान करती है कि केन्द्र सरकार को इस क्रूर कृत्य का परित्याग करने हेतु विवश करने के लिए तत्काल राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारम्भ करें।

कि मिस्र के लगभग ४,५०० वर्ष पुराने पिरामिडों तथा लगभग २,६०० वर्ष पुरानी चीन की विशाल दीवार से भी अधिक प्राचीन, भारत की युगों पुरानी थाती तथा विश्व की प्राचीनतम मानव निर्मित संरचना को विनष्ट करने के घृणित मंसूबों की गंध इस समूची परियोजना से आती है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी हो जाती है कि उक्त नहर परियोजना के निर्माण हेतु अधिकारियों के समक्ष किसी भी धरोहर को नष्ट न करते हुए कई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध थे। उन्होंने न केवल पर्यावरणविदों द्वारा उठाई गई आपत्तियों तथा उस क्षेत्र के हजारों मछुआरों के गंभीर आजीविका-संकट को नजरअंदाज किया है वरन् समुद्री पुरातत्त्वविज्ञान विशेषज्ञों से परामर्श करना भी ठुकरा दिया है। पर्यावरणविदों तथा भू-विज्ञानियों का कहना है कि इस अवरोध के विनष्ट होने से अपने समुद्र तट पर भविष्य में सुनामी जैसी आपदाओं के समय संकट खड़ा होगा। प्रतिनिधि सभा यह स्मरण कराना चाहती है कि औद्योगिकीकरण तथा मेट्रो रेल जैसी विकास परियोजनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले खतरों से आगरा के ताजमहल तथा दिल्ली के कुतुब मीनार जैसे स्थानों को जनता तथा न्यायपालिका के हस्तक्षेप से बचाया गया है। उपर्युक्त दोनों स्थल जहां केवल कुछ शताब्दियों पुराने हैं वहीं रामसेतु की ऐतिहासिकता सहस्राब्दियों पुरानी है। प्रतिनिधि सभा सरकार से मांग करती है कि वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद '५१ क' के अन्तर्गत इस सेतु को संरक्षित स्मारक घोषित करे तथा भावी अध्ययनों हेतु उसे पुरातत्व विभाग को सौंप दे। प्रतिनिधि सभा देशवासियों का आह्वान करती है कि केन्द्र सरकार को इस क्रूर कृत्य का परित्याग करने हेतु विवश करने के लिए तत्काल राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारम्भ करें। इस सभा का सरकार को यह सत्परामर्श है कि वह रामनाथपुरम् जिला न्यायालय द्वारा निर्देशित सुझावों के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का अविलंब गठन कर उसे परियोजना का वैकल्पिक मार्ग तैयार करने का निर्देश दे, जिससे देश के वाणिज्यिक लक्ष्यों की पूर्ति होने के साथ-साथ पवित्र राम सेतु को भी नष्ट होने से बचाया जा सके। ■

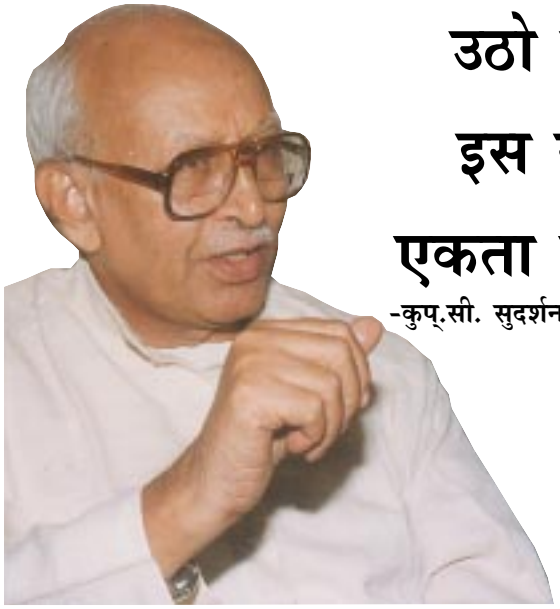

उठो हिन्दुओ, इस संकट में एकता दिखाओ!!

-कुप्.सी. सुदर्शन, सरसंघचालक, रा.स्व.संघ

श्री राम सेतु हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान का अविभाज्य अंग है। सवाल उठता है कि भारत सरकार ने उसे अमान्य कैसे किया? उसे तोड़ने के पीछे उसकी मंशा क्या है? जब से संप्रग का शासन आया है, हिन्दू मान्यताओं और प्रतीकों पर हमले अभूतपूर्व ढंग से बढ़े हैं। राम सेतु को तोड़े जाने का सुरक्षा विशेषज्ञ भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि उससे इस क्षेत्र में विदेशी नौकाओं का आवागमन तो बढ़ेगा ही, अमरीकी दखल का भी विस्तार होगा। अमरीकी दखल के कारण ही जल्दबाजी में

यह भारत के विरुद्ध अमरीकी षड्यंत्र के सामने झुकी कमजोर सरकार का दुष्कर्म है, जिसे रोकना ही होगा। प्रधानमंत्री चाहें तो सही निर्णय ले सकते हैं। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री वे हैं कोई और नहीं। यदि उन्होंने इस मार्ग से राम सेतु का तोड़ा जाना नहीं रोका तो देश में एक विराट जनांदोलन खड़ा होगा। हिन्दू समाज एकजुट होकर सामने आएगा।

राम सेतु तोड़े जाने का कार्य प्रारंभ किया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय से इस परियोजना के संदर्भ में १६ प्रश्न पूछे गए लेकिन उनमें से किसी एक का भी इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार संस्था तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास ने ठीक प्रकार से जवाब नहीं दिया। परियोजना के बारे में न तो पर्यावरण अनुसंधान संस्थान (नेरी, नागपुर) से पूछा गया, न ही सुरक्षा विशेषज्ञों से, न ही सागरीय मामलों के विशेषज्ञों से पूछा गया। ३० जून, २००५ को प्रधानमंत्री कार्यालय को तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास के अध्यक्ष रघुपति ने टालू किस्म के उत्तर भेजे और २ जुलाई को प्रधानमंत्री तथा सोनिया गांधी द्रमुक नेताओं के साथ उद्घाटन करने पहुंच गए। ऐसी जल्दबाजी क्या थी? इस परियोजना का हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी विरोध कर रहे हैं, इस कारण परियोजना पर क्रियान्वयन भी शुरू नहीं हो पाया। दो बार उत्खनन के जहाज भेजे गए, पर राम सेतु तोड़ने वाले जहाज के ब्लेड दोनों बार टूट गए और तीसरी बार उत्खनन जहाज रामनवमी के दिन भेजे गए।

रामसेतु भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परम्परा और आस्था का अविभाज्य अंग है। लेकिन संप्रग सरकार मानो हिन्दू भावनाओं पर कुठाराघात करने के लिए ही सत्ता में आयी लगती है। भारतीय जनमानस प्रांत, भाषा, पंथ, सम्प्रदाय एवं क्षेत्रीय भेदों और सीमाओं को पार करते हुए रामसेतु रक्षार्थ एकजुट, एकप्राण, एकस्वर मुखर हो रहा है। उसकी अन्तश्चेतना में पल रहे क्रोध की अनदेखी करना भूल होगी।

यह भारत के विरुद्ध अमरीकी षड्यंत्र के सामने झुकी कमजोर सरकार का दुष्कर्म है, जिसे रोकना ही होगा। प्रधानमंत्री चाहें तो यह निर्णय ले सकते हैं। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री वे हैं कोई और नहीं। यदि उन्होंने इस मार्ग से राम सेतु का तोड़ा जाना नहीं रोका तो देश में एक विराट जनांदोलन खड़ा होगा। हिन्दू समाज एकजुट होकर सामने आएगा।

■ (पूज्य सरसंघचालक श्री कुप्.सी सुदर्शन से तरुण विजय की बातचीत पर आधारित)

विश्व हिन्दू परिषद सरकार को चेतावनी देना चाहती है कि वह श्रीराम सेतु को तोड़ने से बाज आए वरना इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे।

अशोक सिंहल गरजे-

अयोध्या से रामसेतु तक कांग्रेस कम्युनिस्ट सरकार की नीतियों द्वारा

हिन्दुओं पर आक्रमण का प्रतिरोध करो

विश्व हिन्दू परिषद् के अन्तरराष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंहल उन दिनों अयोध्या में थे जब श्री रामसेतु तोड़ने के समाचार छपे। इस संदर्भ में श्री अशोक सिंहल ने अयोध्या से **तरुण विजय** से बातचीत की, जिसके मुख्य अंश यहां प्रस्तुत हैं।

●आपको लगता है कि अब पुनः जनमत मंदिर के प्रश्न पर आंदोलित होकर भाजपा के साथ खड़ा होगा?

□भाजपा ने उत्तर प्रदेश की कमान श्री कल्याण सिंह के हाथ में देने की घोषणा की है। यदि वह जीतती है तो मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह ही होंगे। इससे कुछ आशा बंधती है। भाजपा पिछले कुछ समय से हिन्दुत्व की ओर जा रही है। देश की राजनीति हिन्दुत्व से जुड़े मुद्दों से प्रभावित हो रही है। इन दिनों जो समाचार आ रहे हैं वे हिन्दू धर्म पर चतुर्दिक आक्रमणों को ही दर्शाते हैं। एक ओर गंगा और सिन्धु नदी के सूखने तथा प्रदूषित होने के समाचार आए हैं, दूसरी ओर सरकार सेतु समुद्रम परियोजना के माध्यम से लाखों वर्ष पुराने श्रीराम सेतु को तोड़ने का जघन्य अपराध कर रही है। ऐसी स्थिति में हिन्दू मानस के भीतर एक गुस्सा धधक रहा है। इन आक्रमणों का हिन्दुओं की एकजुट ताकत से ही उत्तर दिया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि अब हिन्दू वोट बैंक अब फिर से

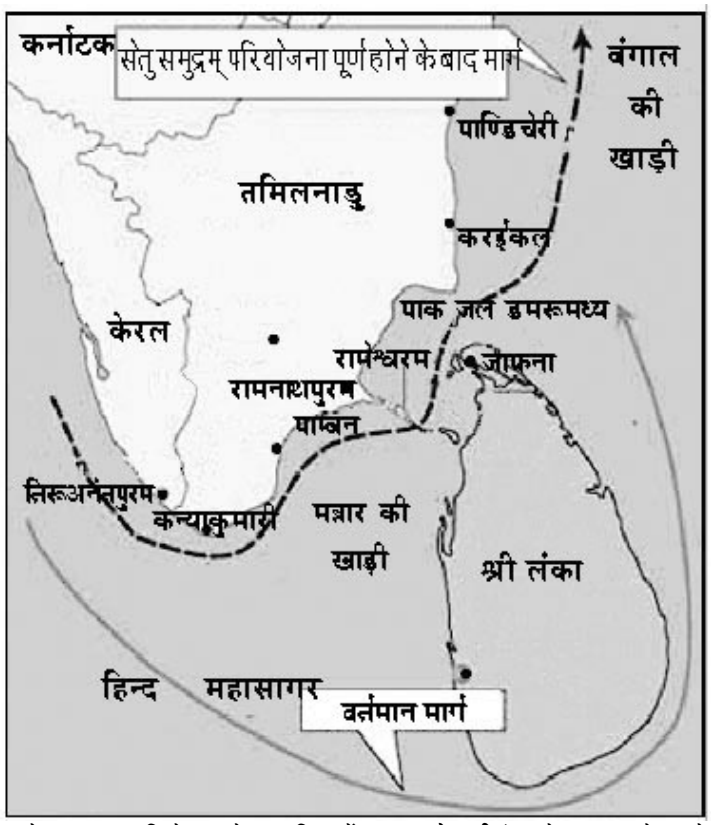

सेतु समुद्रम परियोजना के इस चित्र में भारत और श्रीलंका के मध्य गहरे काले रंग की रेखा सेतु समुद्रम् परियोजना मार्ग दर्शाती है। इसी स्थान पर सागर में रामायणकालीन सेतु होने के उपग्रह चित्र प्राप्त हुए हैं। नक्शे में नीचे दिख रही रेखा इस वक्त जलपोतों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा मार्ग दर्शाती है।

मजबूत हो रहा है। प्राचीन श्रीराम सेतु को सरकार गुपचुप तरीके से तोड़ने की कोशिश जारी रखे हुए है। विश्व हिन्दू परिषद सरकार को चेतावनी देना चाहती है कि वह श्रीराम सेतु को तोड़ने से बाज आए वरना इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। ■

सरकार सेतु समुद्रम परियोजना के माध्यम से लाखों वर्ष पुराने श्रीराम सेतु को तोड़ने का जघन्य अपराध कर रही है। ऐसी स्थिति में हिन्दू मानस के भीतर एक गुस्सा धधक रहा है।

राजनीति से ऊपर उठकर सब हिन्दू एकजुट हों

-स्वामी सत्यमित्रानंद जी, संस्थापक, भारत माता मंदिर (हरिद्वार)

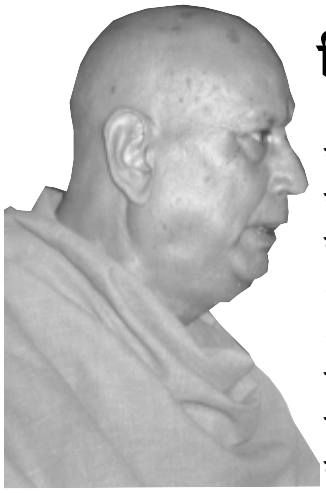

हिन्दुओं की संगठित शक्ति के अभाव के कारण ही अब तक राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया और अब रामसेतु तोड़ने की योजना बन रही है। समझना होगा कि प्रजातंत्र में जनता की शक्ति का ही मूल्य होता है। इसलिए हिन्दुओं पर होने वाले आघात के लिए हम दूसरों को दोष देने की अपेक्षा अपने स्वार्थों का परित्याग कर हिन्दू संगठन में अपनी पूर्ण शक्ति झोंकने का प्रयत्न करें। और जब कोई हिन्दू संगठन या संस्था अपने हितों के संरक्षण की बात करे तो उसमें दूसरे लोग अपनी शक्ति के प्रदर्शन का प्रयत्न न करें। जब जनतंत्र में शक्ति राजसत्ता के हाथ में है और उसके लिए हिन्दू एकजुट हों।

रा.स्व.संघ जैसे हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों को भी समझना होगा कि 'वन्देमातरम् की जय' बोलने वाले राजनीतिक दल तो साथ हैं ही, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी आदि सभी दलों के उन प्रतिनिधियों की खोज करनी होगी जिन्हें हिन्दुओं की भावनाओं पर होने वाले आघातों से पीड़ा होती है। ऐसे लोगों से कहना चाहिए कि भले ही राजनीतिक दृष्टि से आपका चिंतन भिन्न हो, पर हिन्दू आस्थाओं और भावनाओं पर होने वाले कुठाराघात के विरुद्ध आपका स्वर एवं शक्ति हमारे साथ होनी चाहिए। यदि हम बार-बार उनसे ऐसा कहें तो सफलता मिलेगी तथा एक और नया मार्ग खुलेगा।

जहां तक हिन्दू समाज की उदासीनता अथवा सोए हुए हिन्दू समाज को जगाने का प्रश्न है तो उसी कार्य में रा.स्व.संघ पिछले ८० वर्ष से लगा है। अभी श्री गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष में बहुत जागृति आई। देशभर में ६ हजार से अधिक हिन्दू सम्मेलनों में २ करोड़ से अधिक लोग सहभागी हुए। पर हिन्दू समाज का स्वभाव बन गया है

कि वह अपनी आस्था और प्रतीकों के प्रति कुछ समय तक चेतना में रहता है फिर सुप्तावस्था में चला जाता है। इसलिए ऐसे प्रयत्न होने चाहिए कि हिन्दुओं के शौर्य में निरन्तरता बनी रहे। इसके लिए देश की हिन्दू संस्थाओं के अनुभवी महापुरुषों को मिलकर विचार करना चाहिए और विद्वान साधु, संतों, महात्माओं का सहयोग भी लें।

यह बात सही है कि वर्तमान में अनेक चुनौतियां हैं पर यदि देश की प्राचीनता, ऐतिहासिकता का कोई महत्व नहीं होता है तो आखिर वर्तमान संतति उसके लिए बलिदान क्यों दे? क्यों देश को बचाने के लिए युद्ध लड़े जाते हैं, बलिदान दिए जाते हैं? प्रत्येक देश के कुछ आदर्श, प्रतीक, पुरातत्व होता है और उस देश के वासी उसका रक्षण करते हैं। ■ प्रस्तुतिः जितेन्द्र तिवारी

हिन्दू आस्था का सम्मान करें, नया मार्ग तलाशें

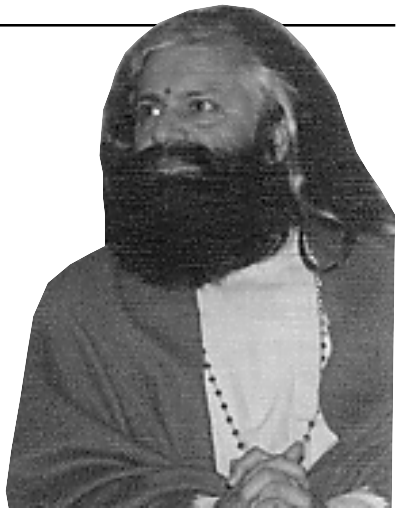

-स्वामी चिदानंद सरस्वती 'मुनि जी',
मुख्य अधिष्ठाता, परमार्थ आश्रम, ऋषिकेश

रामसेतु निश्चित रूप से हिन्दू आस्था का प्रश्न है। हिन्दू धर्म, भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले प्रत्येक प्राणी के मन में ऐसी खबर से पीड़ा स्वाभाविक है। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति हो रही है, उसमें ऐसे तरीके निकाले जाने चाहिए जिससे हमारी संस्कृति और आस्थाओं पर चोट न हो और देश की प्रगति का आयाम भी न रुके। हिन्दू धर्म की तो विशेषता ही है कि वह लोगों के बीच समन्वय का सेतु बनाता है पर हिन्दुओं की आस्था के प्रतीक श्रीराम द्वारा निर्मित सेतु ही जब तोड़ा जाएगा तो उससे जो क्षति होगी उस की पूर्ति कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह ऐसा रास्ता निकाले कि हिन्दू भावनाओं का सेतु भी न टूटे और देश के विकास का मार्ग भी अवरुद्ध न हो।

अयोध्या से लेकर रामसेतु तक हिन्दू भावनाओं पर की जा रही चोट का एक प्रमुख कारण है समाज का भौतिकवादी हो जाना। जब समाज भौतिकवादी हो जाता है तो उसकी आस्था के प्रश्न गौण हो जाते हैं। आज हिन्दुओं के तीर्थस्थल- वृंदावन, गोवर्धन, वाराणसी, हरिद्वार, पुरी, अयोध्या, बद्रीनाथ आदि की स्थिति क्या है? यहां तक हरि की पैड़ी के पास गंगाजी में गंदे नाले का जल छोड़ा जा रहा है और हिन्दू लोग ही ऐसा कर रहे हैं। गंगा हमारे धर्म, संस्कृति और आस्था की जीवन रेखा है, जब हम स्वयं ही उसका संरक्षण नहीं कर रहे हैं, उसे प्रदूषित करने में सहभागी हैं तो फिर अन्य मान्यताओं और विचारधारा के लोगों में इसके प्रति सम्मान का भाव कैसे उत्पन्न होगा? जब हिन्दू स्वयं अपने प्रतीकों, पवित्र स्थलों की पवित्रता के प्रति जागरुकता का भाव नहीं रखेंगे तो बाकी लोग उन पर कुठाराघात करेंगे ही। जहां तक राजनीतिक कारणों से हिन्दू भावनाओं की उपेक्षा का प्रश्न है तो वह सबके सामने है। पर समझना होगा कि राजनीतिक रूप से चुने हुए देशभर में कुल कितने लोग हैं।

लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के कुल मिलाकर १०-१५ हजार प्रतिनिधि होंगे। उनके अपने स्वार्थ और मजबूरियां होंगी। पर उनके अलावा देश में सवा सौ करोड़ से अधिक लोग हैं, वे क्या कर रहे हैं? हमारी मान्यता है कि यह वही सेतु है जो प्रभु श्री राम के नेतृत्व में उनके भक्तों ने निर्मित किया था। नासा द्वारा उपग्रह से खींचे गए चित्र से भी लोगों में यह जागृति आई कि यह वही सेतु है जो लंका पर चढ़ाई के समय श्रीराम ने बनाया। इस कारण से हम सबकी उसके प्रति आस्था है। ■ प्रस्तुतिः जितेन्द्र तिवारी

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.टी. थामस ने कहा-

रामसेतु तोड़ना उचित नहीं

सरकार धार्मिक भावनाओं का सम्मान करे। जिस रामसेतु ने भारत के तटों की रक्षा की उसे तोड़े बिना दूसरा जलमार्ग ढूंढा जाए।

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री के०टी०थॉमस की न्यायिक छवि विश्व प्रसिद्ध है। इस वर्ष उन्हें भारत सरकार ने उनकी न्यायिक शुचिता और न्याय के क्षेत्र में सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया है। उन्होंने ५ अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से यह अलंकरण प्राप्त किया। उन्हें ४ महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील आयोगों का अध्यक्ष भी बनाया गया था। जिनमें से एक केरल में व्यावसायिक महाविद्यालयों में छात्रों की फीस को उचित एवं न्यायिक ढंग से निश्चित करने सबंधी था, दूसरा केरल के सभी विद्यालयों में प्रवेश की सही और जनहितकारी प्रक्रिया तय करने संबंधी था, तीसरा पुलिस व्यवस्था में सुधार के बारे में और चौथा नोएडा में भू आवंटन में हुए घोटाले की जांच का था। इन सभी की जांच उन्होंने निश्चित समय में पूरी की और कभी भी आयोग की अवधि नहीं बढ़वाई। इतना ही नहीं, किसी भी आयोग में कार्य करते समय एक नया पैसा वेतन या भत्ता नहीं लिया क्योंकि उनका कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय से अवकाश के बाद मुझे जो पेंशन मिल रही है वह भी सरकार का धन है अतः मैं सरकार की सेवा के लिए दो बार पैसा कैसे ले सकता हूं। पद्म भूषण अलंकार ग्रहण करने हेतु जब वे दिल्ली आए तो उनसे तरुण विजय की बातचीत के मुख्य अंश यहां प्रस्तुत हैं।

भारत का संरक्षक ईश्वर है और यह पवित्र भूमि है। इसलिए हम संकटों से भी बचते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं।

-के.टी. थामस

● **पद्म भूषण अलंकरण स्वीकार करते समय देश की परिस्थिति के संदर्भ में आपके मन में क्या विचार उठ रहे हैं?**

■ यह पद्म भूषण स्वीकार करते समय मेरे मन में आनंद और प्रसन्नता है। उसका एक कारण यह भी है कि यह बिना मेरी मांग किए या मेरे द्वारा प्रयास किए मुझे प्रदान किया जा रहा है। हालांकि सच यह भी है कि कई बार जो लोग कोशिश करते हैं उनको यह अलंकरण नहीं भी मिलता। जहां तक देश का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि भारत दुनिया की सबसे पावन भूमि है जो स्वयं ईश्वर द्वारा संरक्षित है। मैं अपने व्याख्यानों में कहता हूं कि आजादी के बाद भारत के इतिहास में जो सबसे बड़ी और महान घटना हुई वह भारतीय संविधान का निर्माण कही जाएगी। हम आज जिस स्थिति में है और जिस प्रकार सभी आघातों को झेलते हुए लोकतंत्र और सामाजिक तानाबाना बचाए रख पा रहे हैं वह भारतीय संविधान के कारण ही है। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनमें से सभी में लोकतंत्र, मानवाधिकार, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और सामान्य मुक्त नागरिक व्यवहार धूल धूसरित हुए हैं, इन सभी मूल्यों पर वहां आघात हुए हैं। केवल भारत ही ऐसा देश है जहां ये मूल्य अभी भी पूरी तरह सुरक्षित ही नहीं बल्कि फल फूल रहे हैं।

राम सेतु या सेतु समुद्रम ने सुनामी जैसे तूफानों के समय भारतीय तटों, विशेषकर केरल के तट की रक्षा की है। ऐसे राम सेतु को तोड़ने के पीछे क्या सार्थकता हो सकती है?

भारतीयों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और इस प्रकार का सम्मान किए जाने की यहां परंपरा भी है। जिस बात से धार्मिक भावनाएं और हजारों वर्ष पुरानी परंपराएं जुड़ी हों उस पर आघात नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरी स्पष्ट मान्यता है कि राम सेतु को नहीं तोड़ा जाए तथा इसका वैकल्पिक मार्ग अपनाया जाए।

मैं समझता हूं भारत का संरक्षक ईश्वर है और यह पवित्र भूमि है। इसलिए हम संकटों से भी बचते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं।

● **आप भारत को ईश्वर द्वारा संरक्षित देश कहते हैं, लेकिन उसी भारत में जिन श्रीराम को करोड़ों लोग ईश्वर का अवतार मानते हैं उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से बने राम सेतु को तोड़कर नया समुद्री जलमार्ग बनाया जा रहा है।**

■ मैं बहुत तीव्रता से महसूस करता हूं कि इस प्रकार के प्रकल्पों को भू गर्भीय जांच ही नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं के सम्मान की कसौटी से गुजारकर फैसला करना चाहिए। भारतीयों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और इस प्रकार का सम्मान किए जाने की यहां परंपरा भी है। जिस बात से धार्मिक भावनाएं और हजारों वर्ष पुरानी परंपराएं जुड़ी हों उस पर आघात नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरी स्पष्ट मान्यता है कि राम सेतु को नहीं तोड़ा जाए तथा इसका वैकल्पिक मार्ग अपनाया जाए। वैसे भी मैंने सुना है कि राम सेतु या सेतु समुद्रम ने सुनामी जैसे तूफानों के समय भारतीय तटों, विशेषकर केरल के तट की रक्षा की है। ऐसे राम सेतु को तोड़ने के पीछे क्या सार्थकता हो सकती है? इतने अधिक विशेषज्ञों ने राम सेतु तोड़े जाने के विरोध में अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं तो सरकार किसी दूसरे मार्ग की संभावना क्यों नहीं तलाश करती?■

भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने राम सेतु को तोड़े जाने की सरकार की योजना पर गहन चिंता व्यक्त करते हुए ३० मार्च को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उन्होंने कहा कि धनुष्कोटि के निकट सेतु समुद्रम प्रकल्प के अंतर्गत राम सेतु तोड़ने की योजना संप्रग सरकार द्वारा हिन्दू आस्थाओं पर कुठाराघात का ही उदाहरण है। इस संप्रग सरकार ने रामनवमी के ही दिन (२७ मार्च को) राम सेतु तोड़ने के लिए एक्वेरियस नामक खनन नौका रवाना की।

राम सेतु तोड़कर

हिन्दू भावनाओं को कुचलना चाहती है संप्रग सरकार

-राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

उन्होंने कहा कि राम सेतु शैल निर्मित प्राचीनतम स्मारक है जो, माना जाता है, श्रीलंका जाने के लिए भगवान राम ने बनवाया था। यह न केवल भारतीय संस्कृति और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि वैश्विक विरासत है। विदेशी राज के उन काले दिनों में और भारत-शत्रुओं के द्वारा भी कभी किसी ने इसे छूने की हिम्मत नहीं की थी। मगर संप्रग सरकार राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान करते हुए इस प्राचीन स्मारक को तोड़ने पर तुली है।

धार्मिक और सांस्कृतिक आयामों के साथ ही, लगता है सरकार ने इस प्रकल्प के रणनीतिक पहलुओं को भी नजरअंदाज कर दिया है। इस समय हमारे पास केरल और राम सेतु क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भण्डार है। खनन और वर्तमान नहर मार्ग को खोलने के बाद न केवल थोरियम का भण्डार नष्ट हो जाएगा बल्कि

हम श्रीलंका और भारत के बीच सागरीय सीमा को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्वीकारने के शिकंजे में जकड़ जाएंगे, जिसका हम हमेशा से विरोध करते आए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस प्रकल्प पर जल्दबाजी में किसी अंतरराष्ट्रीय प्रभाव की ओर इशारा किया है। भाजपा खनन कार्य की पूरी तरह जांच करने की मांग करती है।

श्री सिंह के अनुसार इस संवेदनशील क्षेत्र में जहाजों का आवागमन बहुत अधिक बढ़ने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। इस क्षेत्र में सुरक्षा प्रबंधों को बढ़ाना पड़ेगा और इससे प्रकल्प की लागत अनुमान से बहुत अधिक हो जाएगी।

इस स्मारक को ढहाने के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में भी सरकार ने नहीं सोचा है। विश्व विख्यात सुनामी विशेषज्ञ प्रो. टाड मूर्ति ने कहा है कि इसी राम सेतु ने सुनामी से केरल की रक्षा की थी।

श्री सिंह ने भारत सरकार से अपील की है कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत और हिन्दू धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक इस राम सेतु से कोई छेड़छाड़ न की जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सेतु समुद्रम प्रकल्प के विरुद्ध नहीं है बल्कि यह चाहती है कि सरकार वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए उन वैकल्पिक मार्गों पर विचार करे जिनसे राम सेतु को तोड़ने की जरूरत न हो। ■

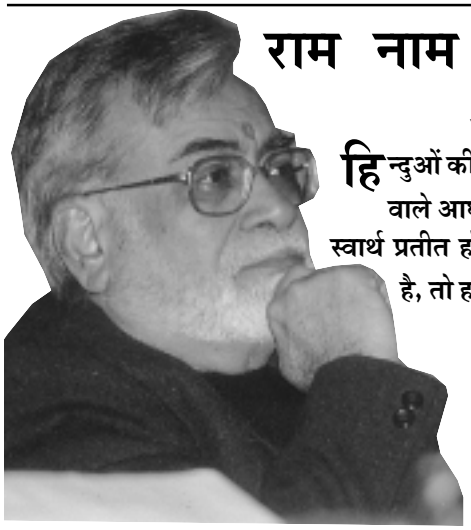

राम नाम के बैरी हैं ये!!

-नरेन्द्र कोहली, वरिष्ठ साहित्यकार

हिन्दुओं की आस्थाओं एवं उसके प्रतीकों पर होने वाले आघातों का एक बड़ा कारण राजनीतिक स्वार्थ प्रतीत होता है। जहां तक राम सेतु का प्रश्न है, तो हमारी मान्यता है कि वह प्रभु राम द्वारा बनाया गया सेतु ही है। हालांकि नासा ने जब समुद्र में डूबे इस सेतु के चित्र को प्रकाशित किया तब यह भी टिप्पणी की कि यह मानव निर्मित नहीं है। यदि इसे मान भी लिया जाए तो नासा द्वारा आंकी गई १६ लाख वर्ष पुरानी धरोहर को तोड़ने का क्या अर्थ है? यदि आप इस पर गर्व नहीं कर सकते। नई तकनीकी का प्रयोग कर उसे समुद्र की सतह पर नहीं ला सकते, तो क्या उसका संरक्षण भी नहीं कर सकते हैं? राम सेतु केवल हिन्दुओं और भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक

धरोहर है। पर चूंकि उसके साथ राम का नाम जुड़ा है, सिर्फ इसलिए उसे तोड़ने की कुचेष्टा की जा रही है ताकि कुछ राजनीतिक लाभ अर्जित किया जा सके।

यह बात सही है कि जबसे यह सरकार आई है तब से हिन्दुओं की आस्थाओं और भावनाओं पर आघात बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि सोनिया गांधी का इस देश और उसकी भावनाओं के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। और मनमोहन सिंह शायद स्वयं को इस देश में दुर्भाग्य से पैदा हुआ मानते हैं जैसे पं. नेहरू मानते थे, अथवा वे सोनिया गांधी की दासता के अधीन हैं। पर वे इस देश का इतना अहित कर रहे हैं कि इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। इसके साथ ही निराशा होती है हिन्दू समाज की प्रतिक्रिया देखकर। इसमें इतना आलस्य और अपने प्रतीकों के प्रति बड़ी उपेक्षा का भाव दिखता है। रामसेतु के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी ही नहीं है। पता नहीं कब यह हिन्दू समाज जागेगा और अपनी आस्थाओं के प्रति एकजुट होकर सजग होगा।

जो लोग वर्तमान चुनौतियों के बीच प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर रामसेतु के संरक्षण के प्रश्न को अनुचित बताते हैं वे या तो अज्ञानी और अबोध हैं अथवा मूर्ख। वर्तमान चुनौतियां और वर्तमान प्रतीकों का संरक्षण अपने स्थान पर उचित है, पर जब आप १७ लाख वर्ष पुरानी अपनी धरोहर का संरक्षण करते हैं तो अपनी उन सब मान्यताओं-परम्पराओं का संरक्षण कर रहे होते हैं जो हमारी संस्कृति का आधार हैं। आखिर वे राम, उनकी कथा ही तो है जो लाखों वर्षों से अनवरत चली आ रही है और सभी प्रकार के आघातों के बावजूद हिन्दू संस्कृति को बनाए हुए है। ऐसे प्रश्न वही लोग उठाते हैं जो राम की बात आते ही, रोटी की बात करने लगते हैं। रोटी भी तो तभी मिलेगी जब आप स्वतंत्र हों। और रोटी मिलने के बाद भी सम्मान चाहिए कि नहीं? समझ नहीं आता कि डायनासोर नामक एक अनदेखे जानवर की छोटी-छोटी हड्डियों को संभाल कर रखा जा रहा है, ५०० साल पुराने ताजमहल को बचाने के लिए कारखानों को हटाया जा रहा है, कुतुबमीनार बचाने के लिए मेट्रो रेल का रास्ता बदला जा रहा है तो इतनी प्राचीन मानवता की धरोहर के प्रति यह उपेक्षा भाव क्यों है? सिर्फ इसलिए कि उसके साथ राम का नाम जुड़ा है? मेरी दृष्टि में रामसेतु को बचाना राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसके लिए जितना भी तीव्र आंदोलन आवश्यक हो, करना चाहिए। ■ प्रस्तुतिः जितेन्द्र तिवारी

सावधान !

रामसेतु तोड़ा जा रहा है-

श्रीराम सेतु में खनन पर डा. मुरली मनोहर जोशी का प्रधानमंत्री को पत्र

श्रीराम सेतु बचाएं, परियोजना मार्ग बदलें

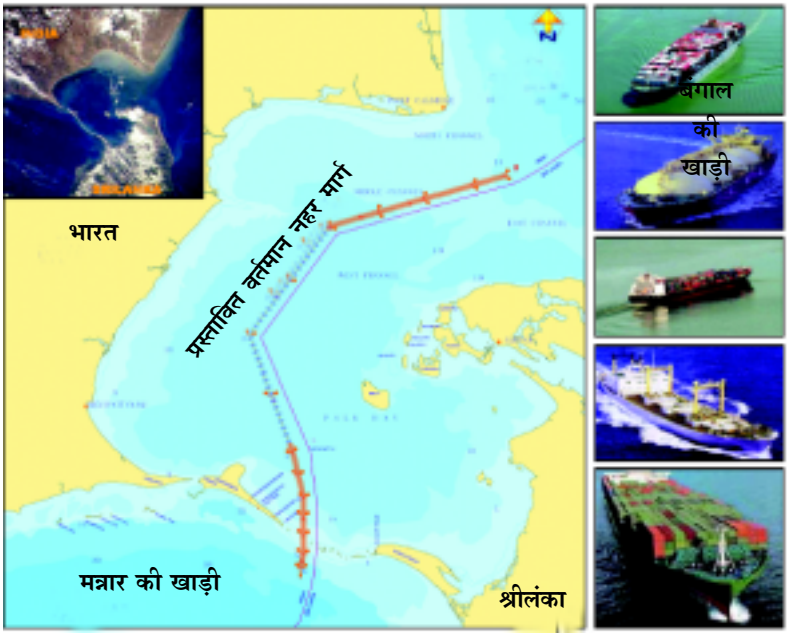

भारत और श्रीलंका के बीच प्रस्तावित नहर मार्ग दर्शाता हुआ मानचित्र

गत २२ मार्च को वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी ने सेतुसमुद्रम परियोजना की पुनर्समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। पत्र में डा. जोशी ने लिखा है- '१९-२२ मार्च के दौरान हमारी तथ्यान्वेषण समिति ने चेन्नै और रामेश्वरम क्षेत्र का दौरा किया था। मैं यहां उस समिति के अन्वेषण की रपट से आपको परिचित कराना चाहता हूं। भारत के लोग श्रीराम सेतु, उसे श्रद्धापूर्वक सेतु मंदिर भी कहा जाता है, पर उमड़ रहे खतरे को लेकर चिंतित हैं। सरकारी अंतःक्षेत्र के अनुसार पाक बे में ८१.८४ प्रतिशत खनन कार्य पुरा हो चुका है और श्रीराम सेतु पर १.४२ प्रतिशत खनन किया जा चुका है। १७४७, १७८८ और १८०४ के नक्शों तथा नासा के उपग्रह चित्रों से इस सेतु की पुष्टि होती है।' उन्होंने श्रीराम सेतु पर कार्य तुरंत रोक देने की अपील की और वैज्ञानिक, तकनीकी और रणनीतिक पुनर्समीक्षा किये जाने की मांग की। भविष्य में सुनामी से रक्षा, पर्यावरणीय और सुरक्षा पहलुओं का आकलन और विशेषज्ञों से सलाह करने के अलावा डा. जोशी ने तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय के सवालों के जवाब देने में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का उल्लेख किया है। पत्र में कहा गया है- 'वास्तव में संचालन समिति द्वारा सुझाया गया मार्ग, जिसे १९९८ में 'नेरी' ने थोड़ा सुधार करके प्रस्तुत किया था, ही सेतु समुद्रम परियोजना का आधार होना चाहिए था। इस प्रस्तावित मार्ग को बदलने के पीछे कोई कारण नहीं बताया गया है और अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के निकट एक रेखा बिना विचार किए खींच दी गयी है। कनाडा के सुप्रसिद्ध सुनामी विशेषज्ञ प्रो० मूर्त्ति ने इस प्रस्तावित जलमार्ग के जरिए केरल में विध्वंस पर गंभीर चिंता जताई है और कहा है कि अगर वर्तमान स्वरुप ही बनाए रखा गया तो भविष्य में आने वाली सुनामी लहरें उसे तबाह कर देंगी। दुर्भाग्य से तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष ने प्रो० मूर्त्ति की इन चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है।'

तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के खिलाफ जांच हो

डा. जोशी ने तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की जांच की मांग की है। अध्यक्ष ने पर्यावरणीय प्रभाव तथा अन्य विश्लेषणों के संबंध में नागपुर की 'नेरी' और चेन्नै की एन.आई.ओ.टी. एजेंसियों से सलाह किये बिना ही प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा व्यक्त संशयों का जवाब दे दिया था। इस जवाब के दो ही दिन बाद इस परियोजना का प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी ने उद्घाटन कर दिया। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना को तैयार करने में

दिखायी गयी लापरवाही और केरल के विध्वंस संबंधी गंभीर चिंताओं की नितांत अनदेखी की गयी। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी इस परियोजना का आकलन करने में

सूझ-बूझ से काम नहीं लिया

चूंकि यह परियोजना महासागर के भीतर से मार्ग बनाने की योजना है इसलिए अत्यधिक सावधानी जरूरी है। इस परियोजना का मार्ग गहरे सागर में है जहां तेज बहाव, बार-बार चक्रवात और अब सुनामी का खतरा बना रहता है। इस संबंध में कोई पुनर्समीक्षा नहीं की गयी और इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

केरल तट को विध्वंस से बचाने के लिए मार्ग का पुनर्निर्धारण हो

मार्ग के उत्तर पश्चिम की ओर पुनर्निर्धारण के बाद निश्चित रूप से आने वाली सुनामी से बचा जा सकता है। श्रीराम सेतु को बचाते हुए मार्ग निर्धारित करने से यह सेतु भविष्य में भी सुनामियों के सामने एक दीवार की तरह काम करेगा। पिछली सुनामी में इस सेतु ने दक्षिणी तटों पर सुनामी का प्रकोप काफी हद तक कम कर दिया था।

डा. जोशी ने श्रीराम सेतु को प्राचीन पवित्र स्मारक बताते हुए उसकी सुरक्षा की मांग की है। पत्र के अंत में वे इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से चर्चा करने के इच्छुक हैं और यदि आवश्यकता हुई तो इसे संसद में भी उठाया जायेगा तथा संसदीय जांच समिति गठित करने की मांग की जायेगी।

■ डा. जोशी के सम्पूर्ण पत्र का अनूदित अंश अगले पृष्ठ पर प्रस्तुत है। -सं.

रामसेतु तोड़ना अधर्म है और सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक

राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सेतु समुद्रम नहर प्रकल्प मार्ग का पुनर्निर्धारण हो

'सबसे पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि भाजपा इस प्रकल्प की विरोधी नहीं है, पर अपने देश की प्राचीनतम सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर चिंतित है, जो मेरे अनुसार वैश्विक विरासत घोषित की जानी चाहिए। हम मानते हैं कि अपनी प्रचुर और विशिष्ट विरासत का संरक्षण हमारे देश की आर्थिक प्रगति जितना ही महत्वपूर्ण है। हम जब वहां दौरे पर थे तब विद्वानों, पत्रकारों, वैज्ञानिकों, पूर्व नौसेना अधिकारियों, मछुआरों के अधिवक्ताओं, स्थानीय नेताओं और पर्यावरण क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं और धार्मिक क्षेत्र के अनेक लोगों से मिले थे, उन्होंने कुछ तथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। इससे नहर का मार्ग, उसका बिना सोचे-समझे निर्धारण और बिना उचित अध्ययन के काम शुरू किए जाने पर सवाल खड़ा हुआ है।

'वस्तुतः १९ मार्च, २००७ की स्थिति, जैसी कि सरकारी अंतःक्षेत्र पर दिखाई गई है, के अनुसार पाक बे- प्रथम खण्ड में ८१.८४ प्रतिशत खनन किया जा चुका है और आदम सेतु पर १.४२ प्रतिशत काम हो चुका है। यद्यपि पाक वे- द्वितीय खण्ड में काम अभी शुरू होना है। यहां ४८ किमी. लम्बे सागर शैलों से निर्मित सेतु के बारे में सब जानते हैं। १७४७, १७८८ और १८०४ के नक्शों सहित नासा और भारतीय दूर संवेदी उपग्रह चित्रों में इसकी पुष्टि होती है। आस्ट्रेलियाई वनपस्तिशास्त्रविद् द्वारा तैयार १७८८ का नक्शा सरस्वती महल लाइब्रेरी, तंजौर में उपलब्ध है, यह रामार सेतु (राम का सेतु) दर्शाता है। १७४७ का नक्शा रामनकोइल-१ (रामेश्वरम् में राम मंदिर) दर्शाता है।

'मुझे बताया गया है कि मशीनों की खराबी के कारण रुका काम एक सप्ताह बाद शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं आपकी अविलम्ब दखल की प्रार्थना करता हूं।'

डा. जोशी इस प्रकल्प पर तुरंत काम रोकने का अनुरोध करते हुए लिखते हैं- 'मैं इस सेतु पर आगे का काम तुरंत रुकवाने का अनुरोध करता हूं ताकि इस प्रकल्प का विस्तृत वैज्ञानिक, तकनीकी, रणनीतिक पुनरीक्षण हो और रामनाथपुरम् अदालत के न्यायाधीश की सलाह के अनुसार बहुआयामी विशेषज्ञ दल गठित करके सागरीय अध्ययनों और भूस्तर पर प्रभावों का ध्यान रखते हुए नहर मार्ग का पुनः निर्धारण किया जाए।

इसके निम्नलिखित कारण हैं-

● जो तबाही १६ दिसम्बर, २००४ को सुनामी ने भारतीय तटों पर की थी उससे बचने के लिए सुनामी निरोधक ढांचा शामिल करते हुए इस प्रकल्प की योजना तैयार की जानी चाहिए थी। पिछले सुनामी में मलक्का स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी के क्षेत्रों में २ लाख लोग मारे गए थे।

● विशेषज्ञों से सलाह किए बिना, गंभीर पर्यावरणीय और सुरक्षा प्रभावों का अंदाजा लगाए बिना, विस्तृत वैज्ञानिक आकलन और सुनामी से रक्षा की चिंता किए बिना ही इस मार्ग का निर्धारण किया गया है।

● तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का गैरजिम्मेदाराना कार्य, जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ८ मार्च, २००५ को व्यक्त की गईं शंकाओं का बहुत हल्केपन और अपूर्ण तरीके से जवाब दिया।

सुनामी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पुनर्मूल्यांकन और वैकल्पिक मार्ग तलाशने का आदेश दें! नीचे दिए गए नक्शे में साफ देखा जा सकता है कि ऐसे ५ वैकल्पिक मार्ग १९६१ के बाद से ही तलाशे गए थे, जिनके कारण राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। वास्तव में तो संचालन समिति द्वारा सुझाया मार्ग (क्र.४) ही इस प्रकल्प के लिए तय किया जाना चाहिए था। इसका कोई कारण नहीं बताया गया कि आखिर यह मार्ग क्यों अचानक अस्वीकार कर दिया गया और नक्शे पर यूं ही एक रेखा अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के बिल्कुल पास खींच दी गई है।'

प्रो.टाड एस. मूर्ति द्वारा व्यक्त गंभीर चिंता और अन्य वैज्ञानिक विषय

'प्रो. टाड एस. मूर्ति के मत के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उठाए गए सवाल और निर्धारित मार्ग पर सुनामी के प्रभाव का आकलन न करना चिंताजनक है। प्रो. मूर्ति सुनामी विषय के विश्वविख्यात विशेषज्ञ हैं और भारत सरकार ने उन्हें सुनामी चेतावनी तंत्र स्थापित करने को कहा है। मगर उनके २१ फरवरी, २००७ के ई-मेल पर लिखी गई बातों से लगता है कि उनके मत अनदेखे कर दिए गए, जो तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट (टी.पी.टी.) के अध्यक्ष के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े करता है।'

कर्तव्य का सही पालन न करने की जांच हो

'८ मार्च, २००५ को भारत सरकार द्वारा उठाए गए गंभीर सवालों का जवाब टी.पी.टी. के अध्यक्ष ने ३० जून, २००५ को दिया। और दो दिन बाद ही बिना विस्तृत पुनर्समीक्षा किए प्रकल्प का उद्घाटन हो गया। ऐसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के प्रकल्प को तैयार करने में ऐसी असावधानी और नहर के वर्तमान मार्ग पर काम बढ़ाने से पूरे केरल के लिए उत्पन्न खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज करना गंभीर चिंता खड़ी करता है। मेरी दृष्टि में, जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही बरतने वाले हर व्यक्ति की जांच हो। चिंता इस

● **विशेषज्ञों से सलाह किए बिना, गंभीर पर्यावरणीय और सुरक्षा प्रभावों का अंदाजा लगाए बिना, विस्तृत वैज्ञानिक आकलन और सुनामी से रक्षा की चिंता किए बिना ही इस मार्ग का निर्धारण किया गया है।** ● **तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का गैरजिम्मेदाराना कार्य, जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ८ मार्च, २००५ को व्यक्त की गई शंकाओं का बहुत हल्केपन और अपूर्ण तरीके से जवाब दिया।**

बात की भी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रकल्प के पुनर्मूल्यांकन की जरूरत नहीं समझी और टी.पी.टी. अध्यक्ष द्वारा दिए अटपटे जवाबों पर विशेषज्ञ राय नहीं ली। अपने एक जवाब में टी.पी.टी. अध्यक्ष कहते हैं- 'नहर का वर्तमान मार्ग खनन स्थल और खनन किए गए मलबे के बीच दूरी कम रखने को ध्यान में रखकर स्वीकारा गया है। संचालन समिति द्वारा सुझाया मार्ग इस मार्ग से कुल १२ किमी. दूर शिंग्ले द्वीप के पास से गुजरता है।' यह गलत प्रस्तुतिकरण इस तथ्य को छुपाता है कि वैकल्पिक मार्ग वास्तव में सागरीय यातायात के लिए दूरी कम करता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि एन.आई.ओ.टी. द्वारा अध्ययन के दौरान लिए गए नमूनों की विस्तृत भूविज्ञानी जांच, परमाणु खनिज अवयवों सहित, की जानी चाहिए थी। टी.पी.टी. अध्यक्ष द्वारा किसी तरह की जांच न किया जाना, कर्तव्य की जनदेखी है।'

यह प्रकल्प सागर के भीतर नहर बनाने का है

'चूंकि यह सेतु समुद्रम प्रकल्प पनामा या स्वेज नहर की तरह भूमि पर बहती नहर नहीं है, अतः इसमें बहुत सावधानी जरूरी है। सागर के भीतर तेज बहाव, बार-बार आने वाले चक्रवातों और सुनामी का खतरा बना रहता है। अगर वर्तमान मार्ग में बदलाव नहीं किया जाता है तो केरल की तबाही की संभावना को देखते हुए इसकी बहुआयामी समीक्षा फिर से होनी चाहिए। मुझे यह बताते हुए खेद हो रहा है कि ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई है।'

केरल तट को बचाने के लिए नहर मार्ग का पुनर्निर्धारण जरूरी

'इस मार्ग को थोड़ा उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ से ले जाना निश्चित ही अगली सुनामी के प्रभाव को कम कर देगा। राम सेतु के बीच से गुजरते मार्ग को निरस्त कर देने से यह सेतु अगली सुनामी के समय एक अवरोधक की तरह खड़ा रहेगा। सेतु के बने रहने से दक्षिण केरल के पश्चिमी तट पर खतरा कम हो जाएगा।'

सेतु मंदिर-वैश्विक विरासत और सहस्त्राब्दी पुराना स्मारक

'नौवहन मंत्री द्वारा राम सेतु पर चिंता प्रकट करने वालों को राष्ट्रविरोधी कहे जाने का मैं कड़ा विरोध करता हूं। प्रस्तावित नहर मार्ग, जो राम सेतु को तोड़ने वाला है, उन करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाता है जो राम सेतु को सेतु मंदिर की तरह देखते हैं, एक तीर्थस्थल, एक पवित्र स्मारक, एक मंदिर की तरह मानते हैं। इस वैश्विक विरासत स्तर के प्राचीनतम स्मारक को ढहाने में भागीदार होना 'अधर्म' है और भारतीय परंपराओं का अपमान करने जैसा है। यह शासन की जिम्मेदारी है कि इस स्मारक, इस सभ्यतामूलक विरासत का रक्षण और संरक्षण हो। भारतीय संविधान की धारा ५१ए ने इसे अनिवार्य बताया है।

भारत के परमाणु कार्यक्रम और सागर में खनिज संसाधनों की खोज पर प्रभाव

डा. जोशी ने वैज्ञानिकों से हुई अपनी बातचीत का संदर्भ देते हुए आगे लिखा है- 'वैज्ञानिकों से बातचीत के दौरान मुझे ज्ञात हुआ कि रामसेतु एक प्राचीन भूगर्भीय रचना है और महासागरीय बहाव के कारण शैल निरंतर बनते रहते हैं और केरल तट पर थोरियम भण्डार निकट होने के कारण पूरे क्षेत्र के भूवैज्ञानिक महत्व का अध्ययन भारत की परमाणु कार्यक्रम नीति को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

रणनीतिक और सागरीय प्रभाव

'जब रामसेतु को नुकसान न पहुंचाने वाले कई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं तो वही मार्ग क्यों तय किया गया जो राम सेतु को बीच से काटते हुए गुजरता है? न पर्यावरणविदों के विचार सुने गए, न भूस्तरविदों और सागरविज्ञानियों के। तट पर रहने वालों की चिंताएं भी नजरअंदाज कर दी गईं। क्या इस प्रकल्प के उद्घाटन से पहले भूरणनीतिक सागरीय प्रभावों पर भारतीय नौसेना से सलाह ली गई? आखिर उस अवरोधक को क्यों तोड़ा जा रहा है जिसने वास्तव में पिछली सुनामी के समय भारतीय तटों की रक्षा की थी? उस अवसर का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा जो जल मार्गों की चौकसी में भारत की

- **१९७०-८० के दौरान भारत और श्रीलंका दोनों ने ही जलराशि को 'ऐतिहासिक' के रूप में पंजीकृत करने की कोशिश की थी।**
- **अमरीका इस दावे को मान्य नहीं करता और निरंतर इन दावों के खिलाफ मत व्यक्त करता रहा है।**
- **अब, भारत अपनी ओर से जल में इस सेतु को तोड़ने जा रहा है, यानी भारत अपने ही दावे से पलट रहा है।**

'जब रामसेतु को नुकसान न पहुंचाने वाले कई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं तो वही मार्ग क्यों तय किया गया जो राम सेतु को बीच से काटते हुए गुजरता है? न पर्यावरणविदों के विचार सुने गए, न भूस्तरविदों और सागरविज्ञानियों के। तट पर रहने वालों की चिंताएं भी नजरअंदाज कर दी गईं। क्या इस प्रकल्प के उद्घाटन से पहले भूरणनीतिक सागरीय प्रभावों पर भारतीय नौसेना से सलाह ली गई? आखिर उस अवरोधक को क्यों तोड़ा जा रहा है जिसने वास्तव में पिछली सुनामी के समय भारतीय तटों की रक्षा की थी?

भूरणनीतिक जिम्मेदारी को सिद्ध कर देता? विदेश नीति में भी एक भारी भूल हुई है, भारत सरकार ने मन्नार की खाड़ी में ऐतिहासिक जलराशि पर अपने अधिकार को पुनस्स्थापित नहीं किया। ये अधिकार आज तक की सभी सरकारें निरंतर जताती आ रही हैं। वर्तमान (भारत) सरकार लगता है कि अमरीकी हितों की पिछलग्गू बनी हुई है और इसलिए बिना विचारे अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के बहुत पास से एक नहर मार्ग तय कर रही है।

निम्नलिखित तथ्यों पर नजर डालें-

● १९७०-८० के दौरान भारत और श्रीलंका दोनों ने ही जलराशि को 'ऐतिहासिक' के रूप में पंजीकृत करने की कोशिश की थी।

● अमरीका इस दावे को मान्य नहीं करता और निरंतर इन दावों के खिलाफ मत व्यक्त करता रहा है।

● अब, भारत अपनी ओर से जल में इस सेतु को तोड़ने जा रहा है, यानी भारत अपने ही दावे से पलट रहा है।

इस ऐतिहासिक महत्व की जलराशि में अमरीका की लगातार दखलंदाजी को देखते हुए साफ है कि वह भारत को अमरीकी हितों के अधीन रखते हुए उससे होरमुज स्ट्रेट के सागरीय यातायात की चौकसी कराना चाहता है। हमें ऐसा नहर मार्ग अपनाना चाहिए जो अमरीका को इस तरह का कोई मौका ही न दे। हमें अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के बहुत निकट का कोई भी मार्ग नहीं चुनना चाहिए क्योंकि वर्तमान मार्ग नहर के दाएं और बाएं तटों पर तट रक्षकों का निर्विरोध आवागमन सुनिश्चित नहीं करता।

पत्र के अंत में डा. जोशी ने पुनः प्रधानमंत्री से अविलम्ब दखल देकर इस प्रकल्प को सभी चिंताओं का समाधान करते हुए लागू करने की अपील की है। डा. जोशी ने

अपने पत्र के साथ कुछ संलग्न भी जोड़े हैं, जो इस प्रकार हैं-

संलग्न-१: प्रो. टाड एस. मूर्ति के विचार

प्रो. मूर्ति कहते हैं- '२६ दिसम्बर, २००४ को हिन्द महासागर में आई सुनामी के दौरान केरल का ठीक दक्षिणी हिस्सा आमतौर पर सुनामी के बड़े प्रकोप से बच गया था। इसका प्रमुख कारण था कि सुमात्रा क्षेत्र से आई सुनामी श्रीलंका के दक्षिण से होते हुए कुछ मात्रा में उत्तरी दिशा की ओर मुड़ गई और इसने केरल तट के मध्य हिस्से पर प्रभाव डाला। चूंकि सुनामी दिशा बदलाव की प्रक्रिया के दौरान गहन गुरुत्वाकर्षी लहर होती है, इसे जो लम्बा मोड़ लेना पड़ा उसके कारण दक्षिण केरल तट बच गया। दूसरी ओर, सेतु नहर को गहरा करने से सुनामी को सीधी चोट का मार्ग मिल जाएगा और यह दक्षिण केरल पर प्रभाव डाल सकती है। २००५ के आखिरी में चेन्नै में मेरी श्री रघुपति (मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रकल्प के प्रमुख) से सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई थी और उसमें मैंने यह बिन्दु उठाया था। मैंने उनसे सेतु नहर के प्रवेश मार्ग में बंगाल की खाड़ी की ओर थोड़ा परिवर्तन करने का अनुरोध किया था ताकि भविष्य में आने वाली सुनामी के दौरान, उसकी ऊर्जा प्रमुखता से सेतु नहर की ओर नहीं बढ़ेगी। श्री रघुपति ने मुझसे कहा कि वे इस मामले को देखेंगे। जब श्री रघुपति जैसा वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी कुछ कहता है तो मैं उस पर भरोसा करता हूं और इस सम्बंध में मेरी अन्य कोई चिंता नहीं है।'

प्रो. मूर्ति ने यह भी उल्लेख किया -'टी.पी.टी. का यह मानना कि मार्ग पुनर्निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है, से मैं इससे पूरी तरह असहमत हूं। मैंने समस्या का पूरा विश्लेषण किया है।' सेतु समुद्रम नहर में कई चीजें वैनकूवर द्वीप की अल्बरनी नहर से मेल खाती हैं और इसी कारण मुझे चिंता है। २८ मार्च, १९६४ को अलास्का में आए भूकंप से उठी सुनामी का सबसे भीषण प्रभाव अल्बरनी नहर के सिरे पर हुआ था जो भूमि पर बहुत भीतर था, खुले तट पर नहीं, जैसा कि सबने अनुमान लगाया था। बाद में मैंने इसका कारण बताया था क्वार्टर लहर प्रतिध्वनि वर्धन।'

● 'नेरी' (पर्यावरण) और एन.आई.ओ.टी. (समुद्र की गहराई) की समीक्षाओं में सुनामी के प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया गया (जो २६ दिसम्बर, २००४ को आई थी यानी 'नेरी' के आकलन के बाद)। ध्यान रहे कि इस क्षेत्र में सुनामी ने सागर की गहराई के स्वरूप को बदल दिया था। मुख्य नमूनों की विस्तृत भूगर्भीय जांच की जाए ताकि परमाणु व अन्य खनिज अवयवों की संभावना का पता चले।

संलग्नक २: सेतु मंदिर पर रामायण और महाभारत के अंश

रामायण में वाल्मीकि राम सेतु के निर्माण पर विस्तार से बताते हैं। महान ग्रंथ महाभारत में राम सेतु के लिए नल सेतु नाम प्रयोग किया गया है। नलसेतु के बारे में वेदव्यास कहते

हैं-'...जो आज भी धरती पर नल सेतु के नाम से लोकप्रिय है, पर्वत समान है, भगवान राम के प्रति श्रद्धा के कारण आज भी खड़ा है (नल विश्वकर्मा के पुत्र थे)।'

मद्रास प्रेसीडेंसी (१८०३) का शासनपत्र दर्शाता है कि इस सेतु को नल सेतु या राम सेतु कहा जाता था। १४८० तक इसने वास्तव में सीलोन को भारत से जोड़ा हुआ था। एक तूफान के कारण सेतु थोड़ा सा टूट गया और तब पैदल आवागमन रुक गया।
संलग्नक-३: देश के परमाणु कार्यक्रम और सागर के भीतर खनिज संसाधनों की खोज पर प्रभाव भाभा एटॉमिक रिसर्च सेन्टर का अन्तःक्षेत्र बताता है-'वर्तमान में भारतीय थोरियम भण्डार ३५८,००० जी.डब्ल्यू. प्रतिवर्ष की विद्युत ऊर्जा है और अगली शताब्दी या इससे भी अधिक की बिजली आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। यू-२३३/थो.२३२ आधारित ब्रीडर रिएक्टर अभी निर्माणाधीन है और भारतीय परमाणु कार्यक्रम की अंतिम थोरियम उपयोग स्थिति में प्रमुख भण्डार की तरह काम करेगा।' वैज्ञानिकों का एक दल सी.एस.आई.आर. (नई दिल्ली) के डा. वी.जे. लवसन के नेतृत्व में क्षेत्र में अन्य अवयवों पर अध्ययन कर रहा है, उसके अनुसार अकेले लगभग ४० मिलियन टन ट्राइटेनियम ५०० कि.मी. तट क्षेत्र में जमा हो गया है। दिसम्बर, २००४ की सुनामी ने सागर के भीतर की संरचना बदल दी है। अतः इस प्रकल्प से जुड़े सभी मार्ग प्रारूपों पर पुनः विचार हो और यह खनिज संसाधनों, जो भारत के परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण हैं, का ध्यान रखते हुए हो। रामसेतु के निकट केरल की ब्लैक थोरियम रेत से निकलने वाली प्राकृतिक रेडियोधर्मिता स्थानीय आबादी में डी.एन.ए. उत्परिवर्तन दर में तेजी ला रही है। इन नए उत्परिवर्तनों में से ज्यादातर ने उसी डी.एन.ए. स्थिति पर चोट की है जो मानव के उदय के पिछले कम से कम ६०,००० सालों में स्वाभाविक रूप से उत्परिवर्तित हुई थी।
संलग्नक -४ : सेतु समुद्रम नहर प्रकल्प के रणनीतिक प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय और ऐतिहासिक जलराशि में अंतर करने वाले अमरीकी नौसेना के निम्नलिखित कार्य निर्देशों पर एक नजर डालें- 'अगस्त, १९७६ का कानून सं. ८० सरकार को अधिकार देता है कि वह जलराशि को ऐतिहासिक घोषित करे। जून, १९७९ का कानून सं. ४१- श्रीलंका तट और सीमा के बीच पाक वे का जल अंतरराष्ट्रीय जलराशि के रूप में माना गया; तट और सागरीय सीमा के बीच मन्नार की खाड़ी की जलराशि ऐतिहासिक जलराशि मानी गई। यह दावा अमरीका द्वारा मान्य नहीं किया गया है। १९९३, १९९४ और १९९९ में मन्नार की खाड़ी में प्रभावशाली अभियान क्रियान्वित किए थे।

यह समझने की जरूरत है कि भारत को इस ऐतिहासिक जलराशि में सागर में गुजरने वाले जहाजों, सागरीय व्यापारियों सहित 'केरल रीफ' और 'एल्गी', पर्यावरणीय सम्पदा आदि, जो लाखों लोगों को आजीविका देती है, की रक्षा के लिए अपनी रणनीतिक जिम्मेदारी जाहिर करनी चाहिए। सेतु समुद्रम प्रकल्प के अंतर्गत ३२,००० टन भार वाले

जहाज ही इस नहर से गुजर सकेंगे। हालांकि अंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्ग का उपयोग करने वाले ज्यादातर जहाज भारी वजन के होते हैं, अतः वे इस नहर से नहीं गुजर पाएंगे। ऐसे में इस प्रकल्प की आर्थिक उपयोगिता क्या है? क्या यह प्रकल्प केवल हल्दिया/पारादीप/विशाखापट्टनम से तूतीकोरिन या फिर फीडर भण्डारण जहाजों तक कोयला पहुंचाने वाले जहाजों के लिए ही बनाया गया है? एक अन्य पहलू है-'अवरोध रहित नहर'। क्योंकि नहर के दोनों सिरों पर किसी तरह की रोक या दीवार नहीं खड़ी की जाएगी तो कोई भी बड़ी लहर इस नहर को तहस-नहस कर देगी। तब इस पर लगाए जाने वाले २,००० करोड़ रुपए का क्या होगा? पता चला है कि खनन यंत्रों के लिए अक्तूबर से दिसम्बर के बीच काम करना असंभव होगा क्योंकि तब चक्रवात का मौसम रहता है। तेज हवाएं और ऊंची लहरें चलती हैं। उस वक्त नहर की देखरेख की बजाय प्रकृति माता की शक्ति से संघर्ष ही होता रहेगा। ■

भाजपा ने राम सेतु रक्षार्थ डा. जोशी के नेतृत्व में ६ सदस्यीय समिति गठित की

सेतु समुद्रम परियोजना के क्रियान्वयन से श्रीराम सेतु के ध्वस्त होने का खतरा बना हुआ है। भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने इस परियोजना से जुड़े विभिन्न आयामों और सरकारी योजना के अध्ययन के लिए डा. मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में एक ६ सदस्यीय समिति गठित की है। डा. जोशी के अलावा इस समिति में तीन सांसद श्री वेदप्रकाश गोयल, श्री गोपाल व्यास और श्री थिरिनाउकरसर तथा तमिलनाडु प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री एल. गणेशन और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री अरुणाचलीसा गुप्ता शामिल हैं। गत १९ मार्च से २२ मार्च के दौरान इस समिति ने धनुष्कोटि और श्रीराम सेतु का दौरा किया और वहां चल रहे जलमार्ग खनन का जायजा लिया। इस दौरे के बाद डा. जोशी ने कहा कि अगर खनन का कार्य इसी तरह जारी रहा तो श्रीराम सेतु ध्वस्त हो जायेगा। ■ प्रतिनिधि

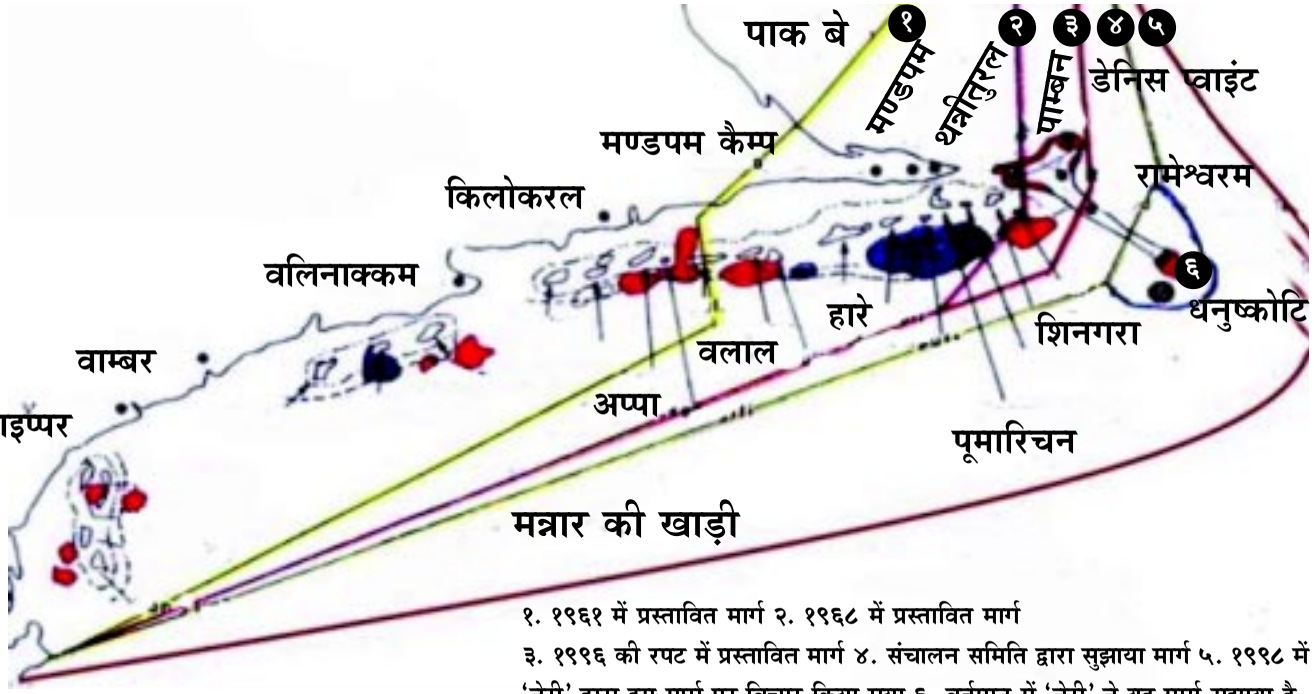

१९६१ से सेतु समुद्रम के लिए सुझाए गए विभिन्न मार्ग

१. १९६१ में प्रस्तावित मार्ग २. १९६८ में प्रस्तावित मार्ग
३. १९९६ की रपट में प्रस्तावित मार्ग ४. संचालन समिति द्वारा सुझाया मार्ग ५. १९९८ में 'नेरी' द्वारा इस मार्ग पर विचार किया गया ६. वर्तमान में 'नेरी' ने यह मार्ग सुझाया है

विशेषज्ञों ने कहा है कि संचालन समिति द्वारा सुझाए मार्ग (क्र.४) पर नहर बनाने से रामसेतु को नुकसान नहीं पहुंचेगा और यह जयादा लाभदायक और योग्य है।

इस समय सरकार क्रमांक ५ वाले मार्ग पर कार्य कर रही है।

सरकार को सद्बुद्धि आए, रामसेतु की रक्षा हो

-कुपुराम, *अध्यक्ष, तमिलनाडु मछुआरा संघ*

श्री कुपुराम ने स्वामी ओंकारानंद जी के निर्देश पर रामनाथपुरम् के न्यायालय में श्री रामसेतु को बचाने हेतु याचिका दायर की है। श्री कुपुराम अधिवक्ता हैं पर तमिलनाडु के सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। वे तमिलनाडु मछुआरा संघ के अध्यक्ष हैं एवं सुनामी सहायता एवं पुनर्निर्माण समिति के प्रदेश संयोजक भी हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, रामनाथपुरम के जिला संघचालक हैं और तमिलनाडु के प्रसिद्ध पांड्यन ग्रामीण बैंक के निदेशक भी हैं। यहां प्रस्तुत हैं रामसेतु एवं सेतु समुद्रम परियोजना के सम्बंध में उनसे की गई बातचीत के मुख्य अंश-

अति प्राचीन और ऐतिहासिक श्रीराम सेतु के क्षेत्र में इन दिनों एक योजना पर कार्य चल रहा है। समुद्र के भीतर डूबे हुए श्रीराम सेतु की चौड़ाई ३ कि.मी. है और लम्बाई ३३ कि.मी.। इस सेतु का पश्चिमी किनारा धनुष्कोटि है और पूर्वी छोर कलई मन्नड (श्रीलंका) तक जाता है। इस क्षेत्र में बड़े मालवाहक जहाजों के लिए एक नहर बनाने की योजना पर काम चल रहा है। गत वर्ष दिसम्बर में उत्खनन विभाग ने कार्य शुरू किया। वहां जैसे ही जहाज 'एक्वेरियस' ने राम सेतु को तोड़ने का कार्य शुरू किया, वह खराब हो गया और उसे ठीक करने के लिए वापस 'शिपयार्ड' में भेजना पड़ा। तब से वहां काम रुका पड़ा है। लेकिन सेतु के आसपास के क्षेत्र में नहर बनाने का कार्य चल रहा है और कुल मिलाकर १६७ कि.मी. लम्बी नहर बननी है। इस समय राम सेतु के उत्तरी भाग में उत्खनन का कार्य चल रहा है।

प्राचीन श्रीराम सेतु को तोड़े जाने के विरुद्ध हमने रामनाथपुरम की निचली अदालत में एक याचिका दायर की। स्वामी ओंकारा नन्द जी एवं स्वयं मेरे द्वारा प्रस्तुत इस याचिका में हमने निषेधाज्ञा अथवा आदेश देने का निवेदन किया था। न्यायालय ने निषेधाज्ञा देने की मांग तो ठुकरा दी लेकिन सरकार एवं सम्बंधित विभागों को यह सुझाव दिया कि भूगर्भीय एवं पुरातात्विक विशेषज्ञों की इस सम्बंध में विशेषज्ञ टिप्पणी से न्यायालय को अवगत कराएं तभी मामले का निस्तारण हो सकेगा। इसलिए अब हमारी मांग है कि विशेषज्ञों के द्वारा इस परियोजना की जांच कराई जानी चाहिए। वर्तमान में सरकार को भी यह पता है कि नहर के निर्माण के लिए चार मार्गों को सुझाया गया था। हमारा कहना है कि राम सेतु

को क्षति पहुंचाए बिना तीन अन्य वैकल्पिक मार्गों का चुनाव करना चाहिए। जो मार्ग कुछ विशेषज्ञों ने सुझाए हैं वे वर्तमान स्वीकृत मार्ग से १० कि.मी. छोटे भी हैं और उन पर नहर के निर्माण का खर्च भी कम आएगा। यह मार्ग भी सरकार के विचार में था, पर इसे छोड़कर उसे स्वीकृत किया गया जिसके लिए रामसेतु तोड़ा जा रहा है। यह कहना ठीक नहीं है कि हमने देरी से विरोध प्रकट किया अथवा काम शुरू होने के बाद आपत्ति उठाई। हम २००१ से ही इस सम्बंध में आवाज उठाते रहे हैं जब सरकार ने इस परियोजना के लिए सर्वेक्षण का काम शुरू किया था। उस समय उन लोगों ने जिस चौथे मार्ग को स्वीकृति देने की बात की थी तब हमने कहा था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर अचानक उन्होंने पहले मार्ग का चुनाव कर उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके लिए उन्होंने हमें लिखित रूप से सूचित भी नहीं किया। इसके विरुद्ध हमने तुरन्त देशव्यापी अभियान शुरू किया और रामसेतु बचाने के लिए ३७ लाख लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम को सौंपा। डा. कलाम ने आश्वासन दिया कि वे निश्चित रूप से सम्बंधित अधिकारियों से इस विषय में बात करेंगे, पर कुछ नहीं हुआ। पिछले दिनों जैसे ही रामसेतु को क्षति पहुंचाने का समाचार आया, इस तटीय जिले रामनाथपुरम् में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। यहां के सभी लोग जाति, पंथ और राजनीतिक मतभेद भुलाकर एक स्वर में विरोध प्रकट कर रहे हैं। देश के सभी रामभक्त इसके विरुद्ध हैं। इस क्षेत्र का मछुआरा समाज इसके विरुद्ध है। यह लोगों का स्वतःस्फूर्त विरोध था। हम जानते थे कि केवल विरोध करने से यह नहीं रुकेगा इसलिए न्यायालय में अपील की। हम इस मार्ग के द्वारा होने वाले आर्थिक विकास और माल वाहन में होने वाली पैसे की बचत के विरुद्ध नहीं हैं, पर हम चाहते हैं कि इसके अतिरिक्त जो वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं, उनका प्रयोग किया जाए।

अब रामसेतु को बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरण और आंदोलन का समय आ गया है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। दो दिन पूर्व ही भाजपा नेता डा. मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में भाजपा सांसदों का एक दल यहां आया था और उन्होंने पूरे मामले का बारीकी से अध्ययन किया। अनेक वैज्ञानिक, पुरातत्वविद्, भूगर्भशास्त्री, मौसम विज्ञानी और समुद्र विज्ञानी यहां आ रहे हैं और रामसेतु एवं सेतु समुद्रम परियोजना का अध्ययन कर रहे हैं। अब राम सेतु बचाने के लिए रा.स्व.संघ ने भी आंदोलन की घोषणा कर दी है। उनकी सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा में इस सम्बंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया है। इसके साथ ही देश के सभी शंकराचार्य, आचार्य सभा एवं सभी पंथों के प्रमुखों ने इस सम्बंध में अपना विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और वह रामसेतु को क्षति पहुंचाने वाली इस परियोजना को रोककर वैकल्पिक मार्ग का चुनाव करेगी। ■ प्रस्तुतिः जितेन्द्र तिवारी

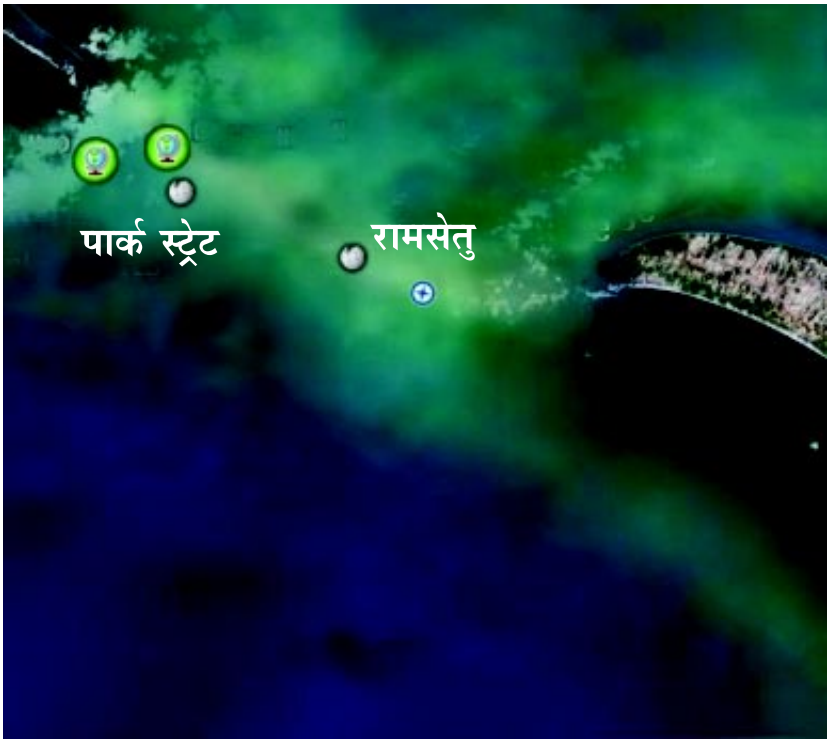

गूगल अर्थ २००७ के उपग्रह चित्र में धनुष्कोटि,
रामसेतु और पार्क स्ट्रेट की स्थितियां दिखाई दे रही हैं

सावधान

रामसेतु तोड़ा जा रहा है!

तर्क और समझ से परे यह सरकारी षड्यंत्र

■ **वी. सुन्दरम,** *आई.ए.एस.*
एसोसिएट संपादक, दैनिक न्यूजटुडे (चेन्नै) एवं प्रथम अध्यक्ष, तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट

कई केन्द्रीय मंत्रियों और सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे लोकसेवकों को बीच बाजार अपमानित किया जाना चाहिए। इसमें जनता की भलाई ही है। सेतु समुद्रम परियोजना छल और राष्ट्रीय शर्म की जीती जागती मिसाल है। प्रधानमंत्री कार्यालय, पोत एवं परिवहन मंत्रालय, तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट ने बड़े सुनियोजित तरीके से सांठ गांठ करके इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है जो मेरी नजरों में

१७४७ में नीदरलैण्ड के नक्शे में मलाबार बोवेन द्वारा दर्शित रामसेतु जिसे राम कोविल (मंदिर) भी कहा जाता था

केवल विध्वंसात्मक परिणाम ही लाएगी।

इस प्रोजेक्ट के द्वारा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने के लिए एक जलपोत मार्ग तैयार करना शामिल है ताकि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच गुजरने वाले जहाज भारतीय जलक्षेत्र में से पेनिन्सुला के इर्दगिर्द समुद्री मार्ग का प्रयोग कर सकें। इससे उन्हें श्रीलंका की परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी। मगर अनेक जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बावजूद दोनों राष्ट्रों के बीच धारा की गहराई केवल १२ मीटर ही रह जाएगी और इसमें से बड़े जहाज गुजर नहीं पाएंगे। केवल मध्यम आकार के या खाली जहाज ही इसमें से गुजर सकेंगे।

'नेरी' ने दिसम्बर २००४ में दक्षिणी भारत में सुनामी की आपदा से काफी पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। 'नेरी' द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रपट सेतु समुद्रम शिपिंग केनाल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिए जाने का सही आधार नहीं हो सकती क्योंकि यह सुनामी से पहले एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित थी।

यह जानना दिलचस्प है कि ८ मार्च २००५ को पर्यावरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा १६ सवाल प्रस्तुत किए गए थे। ये सभी सवाल ८ मार्च २००५ को तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के दफ्तर में भेज दिए गए थे। संभवतः तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को अपने विस्तृत जवाब ३० जून २००५ को भेज दिए थे।

विनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीत,
बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीति!

यह समय महत्वपूर्ण है। इसके दो दिन बाद मनोनीत प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह और 'वास्तविक' प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ने सीधे मदुरै से हवाई मार्ग से आकर २ जुलाई, २००५ को इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। भारतीय जनता इस सुनियोजित घटनाचक्र में कुछ गड़बड़ी की गंध पाती है। शायद इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई रहस्यमयी तथ्यों को छुपाने की कोशिश की गई थी।

जिस आपाधापी में प्रधानमंत्री कार्यालय ने तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट से शंकाओं के समाधान मांगे थे वह एक मान्य प्रक्रिया के उल्लंघन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के उन १६ सवालों के जबाव देने की तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट की योग्यता ही संदिग्ध है। इन बातों से भी इस पूरे प्रोजेक्ट पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय की सभी शंकाएं 'नेरी' को भेजी जानी चाहिए थीं और 'नेरी' को ही दो प्रमुख मुद्दों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ही कहा जाना चाहिए था।

कनाडा के डा० टाड एस० मूर्त्ति दुनिया के जानेमाने सुनामी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भी सेतु समुद्रम केनाल प्रोजेक्ट के विध्वंसकारी परिणामों पर विस्तृत और गंभीर टिप्पणियां की हैं। इस पृष्ठभूमि में, मैं सर्वोच्च न्यायालय से पुरजोर अपील करुंगा कि मेरे इस आलेख को एक जनहित याचिका के तौर पर लेते हुए इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन को रोके। न्यायालय इससे जुड़े सभी सरकारी विभागों को नोटिस जारी करे ताकि भारत की जनता का हित प्रभावित न हो।

यह परियोजना अपने वर्तमान स्वरुप में वैज्ञानिक दृष्टि से अपूर्ण और तकनीकी दृष्टि से निरर्थक है।

यह वास्तव में चौंकाने वाला है कि संचालन समिति में किसी भी खनन विशेषज्ञ, भू विज्ञानी, भूस्तरविद्, तटीय विशेषज्ञ आदि को शामिल करने के बारे में सोचा तक नहीं गया। इस वक्त जो समिति है वह आवश्यक कार्य का केवल दस प्रतिशत ही कर

पाएगी और बाकी नब्बे प्रतिशत भू विज्ञानियों द्वारा ही किया जाना है।

साफ हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय, नौवहन व परिवहन मंत्रालय और तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट में मौजूद निहित स्वार्थियों का कोई सुनियोजित षड्यंत्र शामिल है जिसने अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की तकनीकी सलाहों तक को नजरअंदाज कर दिया।

अगर सेतु समुद्रम जलधारा इस राम सेतु को तोड़कर निकाली गई तो यह पूरे दक्षिण भारत के तटों पर, धनुष्कोटि से आगे केरल तक का हिस्सा भविष्य में सुनामी जैसी आपदाओं का रास्ता साफ कर देगा।

राम सेतु को कोई नुकसान पहुंचाए बिना किसी वैकल्पिक योजना का पुनः अध्ययन किया जाए और रामसेतु के 'नासा' के उपग्रह चित्रों को भी ध्यान में रखा जाए।

एक निर्भीक पत्रकार राधा राजन इस संदर्भ में कहती हैं, 'केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री अंबिका सोनी ने संप्रग सरकार का हिन्दू विरोधी चेहरा फिर से उजागर

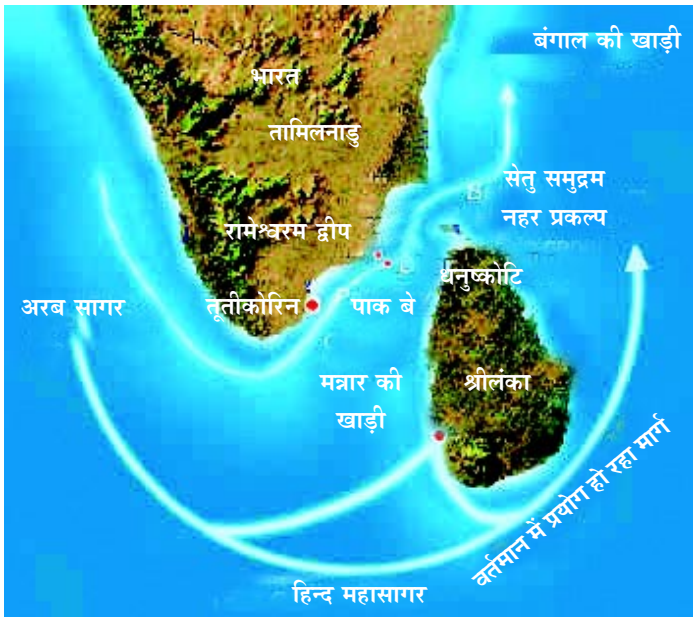

सफेद रेखाओं के माध्यम से सेतु समुद्रम नहर मार्ग का नक्शा। भारत और श्रीलंका के बीच दिख रही सफेद रेखा वह मार्ग है जिस पर खनन शुरू किया गया है और यह राम सेतु को तोड़ते हुए गुजरता है। श्रीलंका के नीचे से घूमकर जाती सफेद रेखा वर्तमान में प्रयुक्त मार्ग दर्शाती है।

'नासा' द्वारा लिए गए इस उपग्रह चित्र में भारत (दाएं) और श्रीलंका के बीच जो पतली रेखा जैसी दिखाई दे रही है, वही है रामायणकालीन श्रीराम सेतु, जो सेतु समुद्रम् प्रकल्प के कारण नष्ट हो जाएगा

किया है। हिन्दुत्व विरोधी राजनीति में यह स्वाभाविक ही है कि हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया जाए। अंबिका सोनी और उनकी पार्टी की अध्यक्ष दोनों ही हिन्दू नहीं हैं और उनसे हिन्दुओं की भावनाओं का सम्मान करने की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। उनके इस प्रोजेक्ट में तमिलनाडु के हिन्दू विरोधी द्रविड़ मुख्यमंत्री सहयोगी हैं। अतः यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत सरकार उस राम सेतु से जुड़े मौलिक ऐतिहासिक तथ्यों से अनभिज्ञ है जिसके अस्तित्व के अनेक अकाट्य प्रमाण मौजूद हैं।

सेतु समुद्रम नहर प्रकल्प (एस.एस.सी.पी.) वास्तविकता से कोसों दूर एक विध्वंसक प्रकल्प है। संप्रग सरकार में कैबिनेट के कुछ मंत्रियों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ-पूर्ति के लिए तमिलनाडु के अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर इसका प्रारूप तैयार कराया है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रकल्प

तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं है। सुनामी विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय भू-वैज्ञानिकों के अनुसार यह योजना असंगत और समझ से परे सरकारी षड्यंत्र है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मार्च, २००५ में इस प्रकल्प से सम्बंधित कई सवाल उठाए गए थे। हैरत की बात तो यह भी है कि भारतीय नौसेना के आला अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। इस सार्वजनिक योजना को कुछ लोग ज्यादा रुचि दर्शाकर अपनी झोली में डालना चाहते हैं। ये ही अब पाक बे के नौसैन्य रणनीतिकार बन बैठे हैं।

सेतु समुद्रम नहर प्रकल्प का मौजूदा प्रारूप निम्नलिखित वैज्ञानिक और तकनीकी कारणों की वजह से अयोग्य है-

१. 'नेरी' के डा. रमेश की अध्ययन रपट में पाक जलडमरू मध्य से निकलने वाले अवसादी पदार्थों के अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही ऐसे किसी स्थान की खोज नहीं की गई जहां खुदाई से निकले मलबे को फेंका जा सके। इस तरह के अध्ययन प्रकल्प के स्थायी रहने में आर्थिक और तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। अध्ययन में इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है कि खुदाई से निकलने वाला मलबा बदलते मौसम में कहां से कहां जा पहुंचेगा।

२. भू-गर्भ विज्ञान का अध्ययन आदम सेतु क्षेत्र में नहर की केवल २० किलोमीटर लंबाई (दूरी) तक ही किया गया है। पाक स्ट्रेट क्षेत्र की भू-गर्भ स्थिति के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस वास्तविकता को समझना होगा कि नहर की लंबाई ५४.२ किलोमीटर होगी। अगर तल पथरीला निकला तो योजना की लागत बढ़ जाएगी और इन चट्टानों के टूटने से पाक जलडमरूमध्य में पर्यावरण पर गहरा असर पड़ेगा। यह 'नेरी' की रपट में साफ लिखा था पर नेताओं ने इसे अनदेखा करके प्रकल्प को राजनीतिक मान्यता दे दी।

३. इस क्षेत्र में वर्ष १८६० से २००० के बीच आए चक्रवातों के ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में और इसके आसपास के क्षेत्रों में चार वर्षों में एक बार चक्रवात आता है। ऐतिहासिक रूप से हमारे पास पर्याप्त आंकड़े हैं जो यह दर्शाते हैं कि इन सभी चक्रवातों से पाक जलडमरूमध्य की खाड़ी और आदम पुल क्षेत्र में सागर के भीतर संरचना में भारी बदलाव होता है। ये चक्रवात अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी व पत्थरों को खाड़ी से ले जाते हैं। 'नेरी' की रपट में इस प्राकृतिक आपदा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है।

४. इस प्रकल्प में इंडोमर के हाइड्रोडीइनैमिक माडलिंग अध्ययन ने चक्रवातों से नहर योजना पर पड़ने वाले असर की अनदेखी की है। अतः हम नहीं जानते कि

चक्रवात के समय नहर पर वैज्ञानिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेगा।

५. कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रो. स्टीवन एनवार्ड इंडोनेशिया के बानडुंग के पेनेलिशियन केलौटन इंस्टीट्यूट टेक्नोलाजी के प्रो. आदित्य रियादी तथा अमरीका और नीदरलैंड और अमरीका के विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए सुनामी के कम्प्यूटरीकृत प्रभाव ने स्पष्ट किया है कि सुनामी लहरों ने २६ दिसम्बर, २००४ को पाक की खाड़ी में भी असर दिखाया था। योजना के नकारात्मक प्रभाव के बारे में अंतरराष्ट्रीय सुनामी विशेषज्ञ प्रो. टाड एस. मूर्ति ने ३० जनवरी, २००५ को प्रधानमंत्री कार्यालय को चेतावनी दी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने योजना के लिए अधिकृत रूप से नियुक्त सलाहकार 'नेरी' को भेजने के बजाय इस मामले को सीधा तुतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट (टी.पी.टी.) के अध्यक्ष को भेज दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ८ मार्च, २००५ को उठाए गए १६ बिन्दुओं का ३० जून, २००५ को जवाब दिया। इसके बाद अचानक २ जुलाई, २००५ को प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने इस योजना की आधारशिला रखी।

दिसम्बर, २००४ से पहले ही 'नेरी' को इस योजना के लिए नियुक्त किया गया था, जबकि दिसम्बर, २००४ में सुनामी ने तमिलनाडु और केरल में कहर बरपाया था। पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए भू-गर्भ विभाग द्वारा २००५ के शुरू में किए गए सर्वेक्षण में बताया गया है कि २००४ में आई सुनामी से तमिलनाडु और अंदमान-निकोबार के तटीय क्षेत्रों में तबाही हुई थी तथा बंगाल की खाड़ी में जलीय जीवों को नुकसान पहुंचा था। योजना से सम्बंधित किसी भी सरकारी संस्था ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जुलाई २००५ में जब इस योजना को लागू किया गया था तब तिरुअनंतपुरम के भूगर्भ अध्ययन केन्द्र के डा. सी.पी. राजेन्द्रन ने पर्यावरण को इससे होने वाली क्षति की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि यह प्राकृतिक भू-क्षरण प्रक्रिया है जिसमें हजारों साल लगते हैं। इस योजना से ये प्रक्रिया बाधित हो जाएंगे। इस योजना के माध्यम से हम एक और प्राकृतिक आपदा को बुलावा दे रहे हैं। इस योजना पर उठाई गई आपत्तियों पर एक स्वतंत्र समिति का गठन किया जाना चाहिए।

प्रो. जी. विक्टर राजमानिकम भारत के सागर तटीय क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। अगस्त २००५ में जब प्रो. राजमानिकम से दिसम्बर २००४ में सुनामी के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इससे कृष्णा नदी के संगम से लेकर कन्याकुमारी तक प्रभाव पड़ा। सुनामी से समुद्र की २०० मीटर गहराई तक तत्व बदल गए हैं। अगर एक अध्ययन से इस तरह के गंभीर परिणामों की जानकारी मिलती है तो हमें समुद्र तल का दोबारा अध्ययन करना चाहिए।

जहाजरानी मंत्रालय द्वारा गठित संचालन समिति ने इस योजना से होने वाली पर्यावरणीय क्षति, जलीय जीवों और सूक्ष्म पादपों पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया है। यह हैरत की बात है कि इस समिति में भूक्षरण विशेषज्ञों, भू-संरचना विशेषज्ञों या मौसम विशेषज्ञों, भू-गर्भ शास्त्री, समुद्र तलीय तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल नहीं किया गया। समुद्रीय जीव विशेषज्ञों और मछुआरों आदि की मौजूदा समिति केवल १० प्रतिशत जानकारी एकत्रित करने में सक्षम है तथा शेष ९० प्रतिशत जानकारी भूवेत्ता व अन्य विशेषज्ञ ही जुटा सकते हैं जो पाक स्ट्रेट के रखरखाव में भविष्य में आने वाली समस्याओं को समझने के लिए जरूरी है।

प्रो. टाड एस.मूर्ति के अनुसार टी.पी.टी. के अध्यक्ष ने फरवरी २००५ के प्रारंभिक दिनों में उन्हें एक फैक्स भेजा जिसमें कहा गया था कि सेतु समुद्रम नहर योजना को फरवरी में अंतिम रूप दिया जाएगा तथा वह इस बारे में उनकी राय २४ घंटे के भीतर जानना चाहते हैं। प्रो. मूर्ति ने एक संक्षिप्त उत्तर दिया कि इस योजना में प्रस्तावित पूर्वी द्वार सही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें टी.पी.टी. के अध्यक्ष की ओर से उत्तर मिला, जिसमें कहा गया कि टी.पी.टी. के विशेषज्ञों ने उनकी राय को बेबुनियाद बताया है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। मूर्ति ने इस टिप्पणी पर कहा कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि टी.पी.टी. ने उनके सुझावों को खारिज किया या नहीं, मुझे उन्हें कोई सफाई देने की भी जरूरत नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों पर ध्यान दें तो साफ होता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, जहाजरानी मंत्रालय और तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट अपने हितों के लिए सेतु समुद्रम नहर योजना के मौजूदा प्रारूप की अनदेखी कर खतरे को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। फिलहाल कार्य में गलत व सही के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह विषयवस्तु और परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। वर्तमान कानून प्रक्रिया में सही तरीके से काम करने की जरूरत है।

यह प्रक्रिया भारत सरकार की अनदेखी को उजागर करती है। इसलिए मेरी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अपील है कि मेरे इस आलेख को एक जनहित याचिका के तौर पर लेते हुए योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगाई जाए। ■

अमरीकी दखल और भारत-श्रीलंका के बीच सागर जल को 'ऐतिहासिक' मान्य करने से ही अमरीकी इनकार का रहस्य खुला। एशियन डेवेलपमेंट बैंक के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी तथा सिन्धु-सरस्वती योजना के निदेशक एवं वर्तमान सूत्रधार **श्री कल्याण रमन** ने वैज्ञानिक तरीके से राम सेतु विध्वंस की पूरी परतें उघाड़ी हैं। उन्होंने **तरुण विजय** से एक विशेष बातचीत में बताया-

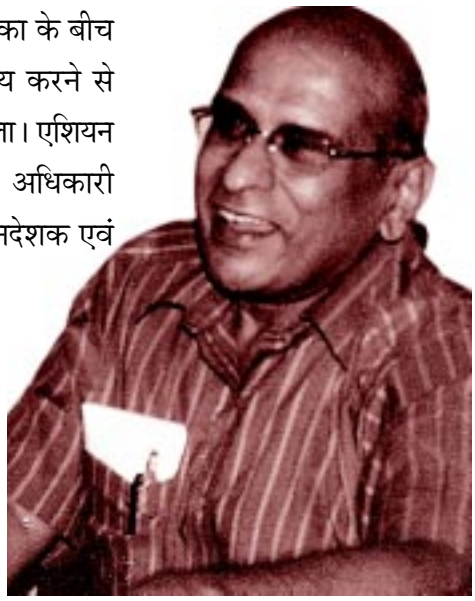

अमरीकी दबाव में झुकी सरकार

१- भारत और श्रीलंका ने पिछले अनेक दशकों से पाक बे, मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट्स को 'ऐतिहासिक' और 'आंतरिक' माना है।

२- अमरीकी इस दावे को मान्य नहीं करते और उन्होंने सदैव इस दावे का विरोध किया है। अमरीका उक्त तीनों क्षेत्रों के सागर को 'अन्तरराष्ट्रीय' मानता है और इन्हें 'ऐतिहासिक' मानने से इनकार करता है।

३- भारत की वर्तमान सरकार ने सेतु समुद्रम जलमार्ग 'अन्तरराष्ट्रीय' सागर सीमा के अत्यंत निकट स्थापित करने का विकल्प चुना है, जिसके कारण राम सेतु (जिसे अंग्रेज और अन्य लोग आदम पुल भी कहते हैं) क्षतिग्रस्त होगा और भारत इस क्षेत्र के सागर को भारत-श्रीलंका के बीच 'ऐतिहासिक' करार देने के अपने पुराने दावे से स्वतः स्खलित हो जाएगा।

४- इसका एक परिणाम यह भी होगा कि जहां श्रीलंका अन्तरराष्ट्रीय सागर सीमा के अपनी ओर इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र रहेगा वहीं भारत के तटरक्षक एवं नागरिक अधिकारी बंधे रहेंगे। क्यों अन्तरराष्ट्रीय सीमा के भारतीय भाग की ओर यह जलमार्ग बनाया जा रहा है जहां से बड़ी सीमा में अमरीकी एवं अन्य विदेशी जहाज गुजरा करेंगे? अब भारतीय तटरक्षकों के लिए श्रीलंका की ओर से इस जलमार्ग की रक्षा करना

अत्यंत कठिन हो जाएगा क्योंकि उन्हें उस स्थिति में अन्तरराष्ट्रीय जलराशि में जाने की बाध्यता होगी जिसके लिए श्रीलंका सरकार और अन्तरराष्ट्रीय कानूनों का बंधन रहेगा।

५- इस बात का कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है कि पाम्बन द्वीप के निकट से यह जलमार्ग क्यों नहीं बनाया जा रहा है? मंडपम और पाम्बन को जोड़ने वाला पुराना पुल भी बना हुआ है जो जहाजों के गुजरते समय ऊपर उठा लिया जाता है और बाद में वापस उस पर से आवागमन शुरु कर दिया जाता है। वह क्षेत्र यदि सेतु समुद्रम जलमार्ग के लिए चुना जाए तो राम सेतु को भी क्षति नहीं पहुंचती।

किसी भी क्षेत्र के सागर को 'ऐतिहासिक' घोषित करने का अर्थ क्या है?

१९५८ में संयुक्त राष्ट्र संघ के सागर विषयक कानूनों पर हुए सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि जिन सागर क्षेत्रों को 'ऐतिहासिक' घोषित किया जाएगा और तद्नुरूप उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्य किया जाएगा, वहां अन्तरराष्ट्रीय कानून लागू नहीं होंगे। इसका अर्थ यह है कि **यदि भारत और श्रीलंका के बीच दोनों देशों की सरकारों के मतानुसार सागर जल 'ऐतिहासिक' मान्य हो जाता है तो वहां अन्तरराष्ट्रीय सीमा नहीं रहेगी और दोनों देशों के मछुआरों एवं नौकाओं तथा तटरक्षकों को एक दूसरे के सागर क्षेत्र में आने की निर्बाध सुविधा रहेगी।** उल्लेखनीय है कि श्रीलंका रामेश्वरम् तथा ट्रिंकोमाली के बीच के सागर को ऐतिहासिक घोषित करने के पक्ष में रहा है। यह घोषणा १५ जनवरी, १९७७ को श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा सागर क्षेत्रीय कानून संख्या २२ (१ सितम्बर, १९७६) के अनुक्रम में की गई घोषणा के अनुच्छेद ७ में दोहराई गई है। साथ ही कहा गया है कि श्रीलंका के ऐतिहासिक सागर जल पाक स्ट्रेट्स, मन्नार की खाड़ी और पाक बे में रहेंगे। इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच २३ मार्च, १९७६ को सागर सीमा निर्धारित करने के बारे में जो करार हुआ उसमें भी इसे मान्य किया गया है।

थोरियम भंडार क्या है?

अमरीका के प्रसिद्ध रक्षा विषयक विचार केन्द्र कानगी एंडोमेंट में टेलिस नामक वैज्ञानिक ने लिखा है कि भारत के पास ७८ हजार मीट्रिक टन यूरेनियम भंडार है जबकि भारत के सम्पूर्ण वर्तमान रिएक्टरों को केवल १४,६४० मीट्रिक टन यूरेनियम की ही आवश्यकता है। भारत के भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताएं थोरियम से पूर्ण होंगी। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल थोरियम भंडार है।

राम सेतु के निकट केरल की सागर तटीय रेत में काला थोरियम आम तौर पर बिखरा पाया जाता है। यह बात भी अमरीकी वैज्ञानिकों के प्रपत्रों में दर्शाई गई है (विशेष जानकारी www.mcdonald. com.ac.uk/genetics/images/ kerala_lowers.jpg) थोरियम विश्व की बहुत ही दुर्लभ धातु है जो सलेटी रंग की

अमरीका का डियागो गार्शिया में सैनिक अड्डा है। वह इस क्षेत्र में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए सक्रिय है। चीन भी ग्वादर से लेकर कोको द्वीप तक तीनों ओर से भारत को घेर रहा है। चीन और अमरीका दोनों भारत की नौ सैनिक स्थिति पर भयंकर दबाव बनाए रखना चाहते हैं।

धात्विक चमक दिखाती है। यह हवा में गर्म करने पर बहुत चमकदार रोशनी से जलती है। इसका नाम थोरियम स्केंडीनेविया के लोकश्रुत युद्ध देवता थोर के नाम पर रखा गया। भारत के लिए थोरियम का अत्यंत सुरक्षात्मक महत्व है। अमरीका की नजर इस थोरियम भंडार पर है। अमरीकी सागर तटीय सुरक्षा व्यवस्था में राम सेतु का ध्वंस आवश्यक है।

होरमुज से लेकर मलक्का की खाड़ी तक भारत की स्थिति यहां के भू सामरिक महत्व की दृष्टि से बहुत प्रमुख है। अमरीका का डियागो गार्शिया में सैनिक अड्डा है। वह इस क्षेत्र में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए सक्रिय है। वह हिन्द महासागर क्षेत्र में भारतीय स्थिति को निरंतर कमजोर करना चाहेगा। यही कारण है कि चीन भी ग्वादर से लेकर कोको द्वीप तक तीनों ओर से भारत को घेर रहा है। जहां चीन और अमरीका दोनों भारत की नौ सैनिक स्थिति पर भयंकर दबाव बनाए रखना चाहते हैं वहीं यह समझ में नहीं आता कि भारत सरकार क्यों इन दबावों के आगे झुकी?

अमरीकी दबाव, असाधारण जल्दबाजी और राष्ट्रीय हितों पर चोट

अमरीकी दबाव के बारे में अब सारी बात स्पष्ट हो चुकी हैं। ८ मार्च, २००५ को प्रधानमंत्री कार्यालय ने तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास के अध्यक्ष रघुपति को सेतु समुद्रम प्रकल्प के बारे में १६ आपत्तियों वाला पत्र भेजा, जिसमें विश्व प्रसिद्ध सुनामी विशेषज्ञ प्रो० टाड एस. मूर्त्ति के विचार भी समाहित किए गए थे।

● २३ जून, २००५ को अमरीकी नौसेना की ओर से एक क्रियात्मक निर्देश जारी किया गया जिसमें भारत और श्रीलंका के मध्य सागर क्षेत्र को 'ऐतिहासिक' जलराशि मान्य करने से इनकार किया गया है।

● ३० जून, २००५ को तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास के अध्यक्ष रघुपति प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों का बहुत टालू और चलताऊ जवाब भेजते हैं।

● २ जुलाई, २००५ को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी सेतु समुद्रम प्रकल्प का उद्घाटन करते हैं।

● स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के पास रघुपति का जवाब पहुंचने से पहले ही

सेतु समुद्रम उद्घाटन कार्यक्रम तय किया जा चुका था, अतः जो जवाब मिला उसकी छानबीन करने या यह जांचने का कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों का संतोषजनक उत्तर दिया गया है या नहीं, समय ही नहीं था। फिर ऐसी असाधारण जल्दी क्यों दिखाई गई?

सुरक्षा सूत्रों के अनुसार अमरीकी नौसेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच के सागर को 'ऐतिहासिक' न मानने का कारण यह है कि अमरीकी इस क्षेत्र को भारतीय प्रभुत्व और एकांतिक नियंत्रण से हटाकर अन्तरराष्ट्रीय अड्डा बनाना चाहते हैं। कश्मीर से लेकर राम सेतु तक वे अपनी पहुंच, प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं। यह तब तक संभव नहीं है जब तक भारत और श्रीलंका के बीच अन्तरराष्ट्रीय आवागमन वैधानिक रुप से स्थापित न हो जाए। यह स्थिति धनुष्कोटि के पास से जलमार्ग निकाले जाने पर अमरीका के लिए संतोषजनक नहीं बनती। वह भारत को अन्तरराष्ट्रीय सागर सीमा तक बांधकर निष्प्रभावी बनाना चाहता है।

● बार-बार भारत सरकार झूठ बोलती है कि राम सेतु को नहीं तोड़ा जा रहा है जबकि १९ मार्च, २००७ को सरकार की अपनी वेबसाइट (सेतु समुद्रम वेबसाइट) में कहा गया है कि पाक बे के प्रथम खंड में १३.५७ किमी० क्षेत्र में ८१.८४ प्रतिशत उत्खनन कार्य कर दिया गया।

तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास के अध्यक्ष रघुपति के खिलाफ सीबीआई जांच हो

८ मार्च, २००५ को प्रधानमंत्री कार्यालय ने सेतु समुद्रम प्रकल्प के बारे में जो गंभीर आपत्तियां उठाईं उनका जबाव सरकारी वेबसाइट के अनुसार रघुपति द्वारा ३० जून २००५ को भेजा गया लेकिन इस बारे में रघुपति ने नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान अथवा चेन्नै स्थित एनआईओटी से कोई सलाह नहीं ली, जो कि सागर जल वनस्पति और उस पर होने वाले प्रभाव एवं परिवर्तनों के संदर्भ में शोध का सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है। स्पष्ट है कि तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास के अध्यक्ष रघुपति ने प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखने का प्रयास किया और नौवहन मंत्री टी०आर०बालू के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया। ■

अपने देश की संस्कृति और विरासत पर शर्मिंदा यह सरकार

■ तरुण विजय

संप्रग सरकार ने आते ही लद्दाख में प्रतिवर्ष होने वाले सिन्धु दर्शन महोत्सव का नाम यह कहते हुए सिंघे खाबब कर दिया क्योंकि उसमें सिन्धु दर्शन नाम से 'हिन्दू दर्शन' की 'बू' आती है। अब वह अपने किसी भी दस्तावेज, अपने शीर्षस्थ पदाधिकारियों के भाषण अथवा सेतु समुद्रम प्रकल्प के किसी भी कागज में राम सेतु नहीं लिख रही है बल्कि आदम सेतु लिख रही है जबकि तथ्य यह है कि पिछले हजारों वर्षों से यह स्थान केवल राम सेतु के नाम से ही जाना गया है। १७४७, १७८८, १८०४ के पश्चिमी नक्शों में इस सेतु को राम सेतु के नाम से अभिहित किया गया है। तंजौर स्थित सरस्वती महल पुस्तकालय में आस्ट्रेलिया के वनस्पति शास्त्री यात्री द्वारा बनाया गया जो नक्शा रखा है उसमें इसे रामार सेतु लिखा गया है। १७४७ के नक्शे में इसे रामन कोविल कहा गया है जिसका अर्थ है राम का मंदिर। यह भी ज्ञातव्य है कि प्राचीन काल से श्री राम सेतु को भक्ति और श्रद्धा के भाव से साक्षात् राम मंदिर भी कहा जाता रहा है। पहली बार राम सेतु को आदम पुल या एडम्स ब्रिज नाम ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त सर्वेयर जनरल जेम्स रेनल ने दिया। भारत सरकार औपनिवेशिक सरकार द्वारा दिए गए नाम को बहुत सहजता से स्वीकार कर रही है लेकिन भारतीय जन मानस में हजारों वर्षों से जो नाम अंकित है वह कहीं भी नहीं रख रही।

सेतु समुद्रम जलमार्ग योजना के बारे में फ्रंटलाइन पत्रिका के १-१४ जनवरी, २००५ के अंक में टी.एस. सुब्रह्मण्यम ने अपनी रपट में लिखा कि इस प्रकल्प से स्थानीय जनता, अल्पसंख्यक विशेषकर मछुआरे बहुत नाराज हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास द्वारा जनता के साथ बातचीत का जो कार्यक्रम रखा गया वह जूतम- पैजार, शोर और सेतु समुद्रम के तीव्र विरोध में समाप्त हो गया। मण्डपम स्थित केन्द्रीय सागर मत्स्य संस्थान में १४ वर्ष अनुसंधान कर चुके सागर वैज्ञानिक डा. आर.एस. मोहन लाल ने कहा कि सागर के तल पर किसी भी प्रकार की हलचल से मत्स्य

... उन्होंने बनाया

रेखांकन: बलराज

... और भगवान इन्हें सन्मार्ग दिखाएं

संपदा में वनस्पति का भयंकर सर्वनाश हो जाएगा। मदुरै स्थित सामुदायिक संगठन न्यास (सोको ट्रस्ट) के श्री ए. महबूब बाचा और एल. लजपतिराय ने कहा कि सेतु समुद्रम के वर्तमान स्वरुप से मन्नार की खाड़ी और पाक बे में तीव्र जल प्रवाह होगा जिससे मण्डपम क्षेत्र में जल का तापमान बढ़ जाएगा और जल के भीतर के जंगल नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकल्प के समर्थन में वे सभी दल उठ खड़े हुए हैं जिनका भारतीय राष्ट्रीयता और हिन्दुत्व के प्रति गहरा नफरत भरा भाव जगजाहिर रहा है जैसे एमडीएमके, द्रमुक, पीएमके, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां। स्वदेशी नौका मछुआरा पंचायत, रामेश्वरमपुरम के अध्यक्ष आर० राज और एफ. जयपाल तथा एक अन्य संगठन के के० थॉमस वास का कहना है कि केवल हमारे गांव में १३०० नौकाएं मछली पकड़ती हैं, हर नौका कम से कम ८ लोगों के परिवार को पालती है। यदि यह प्रकल्प पूरा हुआ तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बरकोड मछुआरा संघ के सांतियागो फर्नांडीस का कहना है कि जब लगातार सागर के तट से रेत हमारे तटों पर ढेर बनाती रहेगी तो हमारा गांव, नौका पालन और जिंदगी सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। जाहिर है जिस प्रकार से यह प्रकल्प अभी चलाया जा रहा है वह देश, समाज, सुरक्षा, धर्म, विरासत और स्थानीय नागरिकों के जीवन के विरुद्ध एक बड़ा आघात है और यह काम कोई औपनिवेशिक सरकार नहीं बल्कि अपने ही लोगों द्वारा बनी वह सरकार कर रही है जिसके मानस की जड़ें स्वदेशी में नहीं बल्कि औपनिवेशिक दासता में पैठी हैं। ■

श्रीराम सेतु

भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी से होते हुए लगभग ३० किलोमीटर लम्बा ऐसा क्षेत्र है जो सागर शैलों से पुल के समान आच्छादित है। इसे प्राचीन काल से श्रीराम सेतु के नाम से जाना जाता है। न केवल लोकमान्यताओं बल्कि पुराविदों के शोध से भी यह जानकारी मिलती है कि यह ३० किलोमीटर लम्बा श्रीराम सेतु १७ लाख वर्ष पुराना है। कुछ वर्ष पहले अमरीका के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान 'नासा' ने उपग्रह द्वारा खींचे चित्र जारी किए थे। उन चित्रों से पुनः एक बार यह प्रसंग प्रमुख हो उठा। पांच हजार वर्ष से भी पहले जो हिन्दू ग्रंथ रचे गए उनमें श्रीराम सेतु का बहुत प्रेरक, रोचक और महिमावान वर्णन मिलता है। तिरुचिरापल्ली स्थित भारतीदासन विश्वविद्यालय के पुरातत्व शास्त्रियों और वैज्ञानिकों ने शोध के उपरांत अपनी रपट में लिखा है कि यह श्री राम सेतु ३,५०० वर्ष पुराना है। लेकिन कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने लिखा है कि सागर के आरोह और अवरोह का वैज्ञानिक अध्ययन करने के उपरांत यह पता चलता है कि ईसा पूर्व छठी सहस्त्राब्दी में सागर का जलस्तर दस से बीस मीटर तक उठ गया था। अतः उससे पूर्व निश्चित रुप से जिस शैल खंड को श्रीराम सेतु कहा जाता है वह भारत से श्रीलंका तक पैदल जाने का एक व्यावहारिक मार्ग रहा होगा।

हाल ही में भारत सरकार ने अरबों रुपए का सेतु समुद्रम नौका नहर प्रकल्प स्वीकृत किया है जिसका उद्देश्य है मन्नार की खाड़ी से होते हुए समुद्री नौकाओं के आवागमन का जलमार्ग तैयार करना। यह जलमार्ग तैयार करने के लिए धनुष्कोटि के पास श्रीराम सेतु के अंतिम छोर पर शैल खंडों को तोड़ना पड़ेगा ताकि वहां से बड़े समुद्री जहाज आसानी से पार हो सकें। इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि श्रीराम सेतु नाम से प्रसिद्ध शैल खंड, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहासकारों ने आदम पुल का नाम दिया, तोड़कर नौकाओं के लिए जलमार्ग सुगम बनाने से तीस घंटे का नौवहन समय और चार सौ किलोमीटर की श्रीलंका द्वीप के चारों ओर की जाने वाली यात्रा बच जाएगी। लेकिन यह तर्क देश के हिन्दू संगठनों और भारतीय सांस्कृतिक गौरव से जुड़े विभिन्न संस्थानों को स्वीकार्य नहीं है। अनेक ऐसे संगठन हिन्दू संवेदनाओं और भारतीय विरासत के विरुद्ध इस सबसे भीषण और पाश्विक आक्रमण के विरुद्ध खड़े हो गए हैं जो हिन्दू बहुल देश में, हिन्दू बहुमत द्वारा चुनी सरकार के अधिकांश हिन्दू नेता और अधिकारियों द्वारा तोड़ा किया रहा है। केवल एक ईसाई प्रमुख राजनेता के हाथों में सत्ता की बागडोर आ जाने से देश के राजनीतिक और प्रशासनिक चरित्र में कितना अंतर आ जाता है, यह इसका भी एक उदाहरण है।

(पाञ्चजन्य सम्पादकीय, १ अप्रैल, २००७)

इस पुस्तिका की सामग्री

पाञ्चजन्य द्वारा सप्रेम सौजन्य से

विक्रम सम्वत् : 2064

प्रकाशक :
सुरुचि प्रकाशन
केशवकुंज, झण्डेवाला,
नयी दिल्ली-110055
दूरभाष : 23514672

मुद्रक :
निशा एन्टरप्राइजेज
29-शास्त्री पार्क, चन्द्र नगर
दिल्ली-110 051
मूल्य : 7 रुपये

पृष्ठ सज्जा एवं रूपांकन–मंगल सिंह नेगी, राजपाल सिंह रावत, जनार्दन सिन्हा

ISBN-81-89622-31-5